শর্মা হার্ডওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 206 | गुवाहाटी | बुधवार, 26 फरवरी, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 12 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

कार्बी आंगलांग और बाक्सा जिले में एडवांटेज असम 2.0 समझौता ज्ञापन... पेज 3

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से छोटे शहरों को मिला विकसित होने का मौका : मुख्यमंत्री पेज 4

अपमान याद कर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की आंखें छलकी पेज 5

बजट सत्र : सपा सरकार में हर काम को समाजवादी नाम दिया जाता था, जबकि... पेज 8

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन से जुड़ी और खबरें पृष्ठ 12 पर

पीएम मोदी ने किया एडवांटेज असम 2.0 का आगाज, कहा–

पूर्वोत्तर की भूमि से नए भविष्य की शुरुआत

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गज, भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुख समेत कई छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि, ये दो दिवसीय शिखर सम्मेलन गुवाहाटी के खानापारा में मौजूद वेटरनरी कॉलेज फील्ड में आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जी रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम के संभावना और प्रगति से जोड़ने का एक महा अभियान है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा– इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर हमारा ये नॉर्थ-ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है...मैं असम सरकार को, हिमंत विश्व शर्मा जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 2030 तक असम की अर्थव्यवस्था 143 अरब डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने निवेशकों से राज्य की विकास यात्रा हिस्सा बनने का आग्रह भी किया। यहां दो दिवसीय *एडवांटेज* असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य अब *सबसे अशांत* से *सबसे शांत* राज्य बन गया है। उन्होंने दावा किया, इस साल राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 15.2 प्रतिशत होगी। यह 2030 तक 143 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सीएम ने 60 से अधिक देशों के मिशन प्रमुखों और राजदूतों, विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और देश के उद्योग जगत के नेताओं की मौजूदगी में कहा कि मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम असम में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अच्छा काम और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करेंगे। कृपया यहां आएं और निवेश करें। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से राज्य में पुनरुत्थान देखा गया है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण, बांस और टिकाऊ फसल और खाद्य एवं पेय पदार्थ समेत कई अन्य कई विषयों पर खास नजर है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 61 देशों के राजदूत भी असम में मौजूद हैं। वे रविवार को असम पहुंचे थे। जिसके बाद अलग-अलग देशों के राजदूतों ने सोमवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस यात्रा के लिए राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उधर डबल इंजन की सरकार की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार में असम की अर्थव्यवस्था दोगुनी -शेष पृष्ठ दो पर

चिकन नेक को मजबूत करने का मोदी सरकार के पास है रोड मैप : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के पास एक रणनीतिक रोडमैप है, जो पूर्वोत्तर के *चिकन नेक* क्षेत्र को अस्थिर करने वाली चुनौतियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने एडवांटेज असम 2.0 कार्यक्रम में कहा कि सिलिगुड़ी कॉरिडोर न केवल सामरिक रूप से, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस पर बार-बार मंडराते खतरों का जिक्र किया और सरकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम पूरे देश से चिकन नेक के माध्यम से जुड़ा है। यह क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि कई राष्ट्रविरोधी ताकतें इस कड़ी को तोड़ने की धमकी देती रही हैं। लेकिन, अब रेल मंत्री ने इस मार्ग पर कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की घोषणा की है। यहां चार नई रेलवे लाइनें बनाई जाएंगी और सही समय पर दो और रेलवे लाइनों की भी घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तरी बंगाल में स्थित यह संकरा भूभाग पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल क्षेत्रीय स्थिरता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

असम में निवेश की बाढ़, 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट घोषित

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में औद्योगीकरण की बयार तेज हो गई है। एडवांटेज असम 2.0 के पहले ही दिन राज्य को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रिलायंस, अडानी, टाटा और वेदांता सहित देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और असम में निवेश की नई संभावनाओं पर चर्चा की। असम में निवेश का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने उद्घाटन भाषण में कहा कि असम कभी देश के अशांत राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब यह देश के सबसे शांत राज्यों में से एक बन चुका है। इस सकारात्मक बदलाव के कारण देश-विदेश के बड़े उद्योगपति असम में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे असम एक प्रमुख निवेश केंद्र बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी ने 2018 में एडवांटेज असम के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था, जिसे बढ़ाकर अब 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने असम को अगला *गुजरात* बनने की संभावना जताई और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की। बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा घोषित प्रमुख निवेश में रिलायंस असम में 800 से अधिक नए खुदरा स्टोर खोलने और राज्य के खाद्य और गैर-खाद्य उत्पादों के लिए एक नया बाजार विकसित करने की योजना बना रहा है। इससे असम के कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। इसके अलावा, अडानी ग्रुप गुवाहाटी हवाई अड्डे के बाद अब असम के अन्य परिवहन क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। इससे स्थानीय परिवहन और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इन निवेशों से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्लांट से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि रिलायंस और अडानी के प्रोजेक्ट्स से हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। गौतम अडानी ने अपने भाषण में कहा कि असम अब उसी रास्ते पर बढ़ रहा है, जिस पर 2003 में गुजरात ने औद्योगिक -शेष पृष्ठ दो पर

असम की अर्थव्यवस्था 2030 तक 143 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगी : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2030 तक 143 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है। *एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन* के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने असम के उथल-पुथल से शांति की ओर परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इस वर्ष 15.2 फीसदी की अनुमानित जीडीपी वृद्धि के साथ, शर्मा ने निवेशकों को असम के सुधरते कारोबारी माहौल का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने वैश्विक राजनयिकों, विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों और भारतीय उद्योग जगत के नेताओं सहित दर्शकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। -शेष पृष्ठ दो पर

ऐसा लगता है कि यह असम का समय है : अनिल अग्रवाल

गुवाहाटी। मंगलवार को मेगा बिजनेस शिखर सम्मेलन एडवांटेज असम 2.0 के शुरू होने पर, खनन प्रमुख वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश लाने का श्रेय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को दिया। अग्रवाल ने सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से कहा कि असम के मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वह प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस तथा रिफाइनरियों में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह असम का समय है। उन्होंने पूर्वोत्तर में व्यापार के माहौल को *सुंदर* बताया। उन्होंने सरकार और स्थानीय -शेष पृष्ठ दो पर

अशांत से सबसे शांतिपूर्ण राज्य में तब्दील हुआ असम : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि कभी उग्रवाद और अशांति से त्रस्त यह राज्य अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे शांतिपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए सीएम शर्मा ने राज्य में हुए परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने असम के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया। सीएम ने कहा कि असम ने एक तरह से दशकों तक आंदोलन और उग्रवाद देखा है। 2016 के बाद असम ने पुनर्जन्म का अनुभव किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में असम एक शांतिपूर्ण राज्य बन गया है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कभी असम को देश के सबसे अशांत इलाकों में माना जाता था लेकिन अब यह देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य बन गया है। इसके बाद सीएम शर्मा ने असम में कई प्रमुख बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया, जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परियोजनाओं में हाल ही में शुरू की गई टाटा-डोरा सेमीकंडक्टर सुविधा और नामरूप में 1.2 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता वाला एक नया ग्रीनफील्ड उर्वरक संयंत्र शामिल है, जो असम के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। शर्मा ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 2018 में 3 से 4 फरवरी को आयोजित एडवांटेज असम के पहले संस्करण को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान प्रधानमंत्री के आशीर्वाद -शेष पृष्ठ दो पर

असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा रिलायंस : अंबानी

गुवाहाटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी अगले पांच साल में असम में पांच अलग-अलग क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। *एडवांटेज असम* व्यापार शिखर सम्मेलन में अंबानी ने कहा कि यह पैसा असम को प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए तैयार करने के लिए निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 के निवेश शिखर सम्मेलन में मैंने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। तब से निवेश 12,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। यह राशि चौगुनी हो जाएगी -शेष पृष्ठ दो पर

असम एडवांटेज 2.0 के लिए विभिन्न देशों से आए विदेशी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लेने से पहले कामाख्या मंदिर में प्रार्थना किया। फोटोः दशरथ डेका।

इंडो-भूटान आर्थिक सहयोग और गेलगेलफू माइंडफुलनेस सिटी पर सत्र आयोजित

जीएमसी एकता और साझा समृद्धि का प्रतीक : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0: इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के तहत आयोजित इंडो-भूटान आर्थिक सहयोग और गेलगेलफू माइंडफुलनेस सिटी... आपसी सहयोग के अवसर सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर भूटान सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री योंतेन फुंतशो भी उपस्थित रहे। सत्र में असम और भूटान के गहरे ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को रेखांकित करते हुए, व्यापार, कनेक्टिविटी, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के नए अवसरों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-भूटान संबंध आपसी सम्मान और समझ के ठोस आधार पर निर्मित हैं और यह मित्रता केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि साझा मूल्यों का उत्सव भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूटान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक मित्रता आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी। गेलगेलफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) परियोजना पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना भूटान और भारत के बीच एकता और साझा समृद्धि का प्रतीक बनेगी। उन्होंने इस परियोजना के विकास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग की सराहना की और -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

भारत को 2027 तक बनाएंगे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था : अमित शाह

भोपाल (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह मंगलवार को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना है। बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे भाजपा सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहां विकास के बड़े काम हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह की कार्ययोजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल में बुलंद इमारत की नींव डाली गई है, इससे देश के विकास के नए आयाम खुलेंगे। बैंकिंग सेक्टर में दस साल के अंदर 56 करोड़ लोगों को बैंकिंग उपलब्ध कराने का काम किया। देश में 10 सालों में हवाई अड्डे 74 की जगह 157 हो गए हैं। जो सेक्टर दुनिया की अर्थव्यवस्था तय करने वाले हैं, ऐसे सेक्टर का फाउंडर भारत बना है। चाहे वो एआई हो या दूसरे सेक्टर। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 20 साल के शासन में आज यहां 5 लाख किमी रोड नेटवर्क है। छह हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावॉट की ऊर्जा क्षमता है। इसमें से 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी है। देशभर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा पैदा करने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए भी मप्र महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। एमपी में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रचर यहां बन चुका है। ईको सिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया। आने वाले दिनों में मप्र में कृषि और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को आगे ले जाने में टीएम एमपी कामयाब होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिया है कि आपको मध्यप्रदेश में भरोसेमंद प्रशासन मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि कोई भी समूह या कंपनी जब अपने एक्सपेंशन के लिए स्थान तय करता है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है, जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहां हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रचर यहां बन चुका है। ईको सिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया। मार्केट का एक्सेस भी मप्र से ज्यादा किसी स्टेट को उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पारदर्शी शासन ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित किया है। यहां लैंड भी है, लेबर्स फोर्स भी है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उद्योग की संभावनाएं और अवसर हैं, शिक्षित युवा हैं और स्किल्ड वर्क फोर्स भी है। हर तरह से मप्र इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा आकर्षक केंद्र बना हुआ है।

बेलगुरी 17 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक सड़क दुर्घटना

धुबड़ी (हिंस)। जिला के बेलगुड़ी में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर एक भयावह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक देखकर स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत आगमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायलों की पहचान धुबड़ी चर निवासी बहादुर अली और बेलगुड़ी निवासी आयनाल हक के रूप में हुई है। बहादुर अली की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें धुबड़ी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, बाइक (एएस17के-6504) आगमनी से गोलकगंज की ओर जा रही थी, इसी बीच बेलगुड़ी ईंट भट्ठे के सामने एक पैदल यात्री को टक्कर मारी दिया। जिसके चलते दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आगमनी पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर एक प्रथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

हेरोइन समेत एक तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की फैंसी बाजार पुलिस ने हेरोइन की तस्करी मामले में शामिल एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पान बाजार थाना क्षेत्र इलाके के फैंसी बाजार पुलिस चौकी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन नंबर रेलवे गेट इलाके के ऊषामाटी इलाके में अभियान चलाकर अमीर हम्जा (30, बरपेटा) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया ड्रग्स तस्कर क पास से पांच प्लास्टिक की छोटी-छोटी सीसी में भरकर रख गए 6.60 ग्राम हेरोइन समेत बरामद किया गया।

अंत्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से शक्कर देने पर हो रहा विचार

जयपुर (हिंस)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में अन्त्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरान्त उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बन्द की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी का आवंटन किया जाता था। वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई नीति के तहत एक जून 2017 से अन्त्योदय परिवारों को एक किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10816.66 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गई। इसी प्रकार 2020-21 के प्रथम त्रैमास में 1520.30 मैट्रिक टन की खरीद की गई। इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2021 को चीनी का आवंटन आदेश जारी किया गया था, उसके बाद कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

नशे के खिलाफ रंगिया पुलिस की तलाशी अभियान तेज, दो गिरफ्तार

रंगिया (विभास)। रंगिया में नशे के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान में पुलिस को एकबार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सुचना के आधार पर रंगिया थाना प्रभारी नवजीत नाथ और नगर परिदर्शक बिष्णु ज्योति बोरा ने कारवाई करते हुए सोमवार की रात करीब 8.30 बजे वार्ड नंबर 1 स्थित तेतेलीगुड़ी में एक स्कूटी को रोककर तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने लगभग 8 किलोग्राम संदिग्ध गांजे के साथ उक्त स्कूटी में सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस द्वारा इस अभियान में स्कूटी (पंजीयन नंबर एएस 25 डब्ल्यू 7368) और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए है। अभियान में खाईरूल इस्लाम उम्र 43 वर्ष, काजिगांव (रंगिया) और खुरसेन अली, उदियाना (रंगिया) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों को जब्त किए गए सामान के साथ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए रंगिया थाने लाया गया है।

জাননী

শিশুটিৰ নাম ঃ- অজ্ঞাত
পিতৃৰ নাম ঃ- অজ্ঞাত
মাতৃৰ নাম ঃ- অজ্ঞাত
বয়স ঃ- ১ বছৰ ৬ মাহ (আনুমানিক)
ঠিকনা ঃ- অজ্ঞাত

এই শিশুটি যোৱা ১২/১০/২৪ তাৰিখৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটৰ অধীনত থকা (Special Adoption Agency (SAA)ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। বহু সন্ধান কৰিও এই শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে উক্ত শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ সন্ধান পায়, তেন্তে জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট, শোণিতপুৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল।

যোগাযোগৰ ঠিকনা ঃ-
জিলা শিশু সুৰক্ষা, শোণিতপুৰ (১৯)
চান্দমাৰী বিহু ফিল্ডৰ ওচৰত
ৱাৰ্ড নং ১৯
যোগাযোগ নম্বৰ - ৭০০০২০৮১৪৭৪,
৯৯৫৭৩৯১৩০৪২

-- Janasanyog /D/ 13004/24/26-Feb-25

Child Protection Officer
Nion-Institutional Care
ODCPU Sontpur

अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी दवाएं

नई दिल्ली। दवाओं के दुरुपयोग को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि दवाएं बिना डाक्टर की पर्ची के न बेची जाएं। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य दवा नियामकों के साथ बैठक में यह भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नियामक मानकों को मजबूत किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के अवैध इस्तेमाल पर लगाम लगाने और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नियामक क्षमताओं को मजबूत करने के तरीकों पर विचार करने के लिए राज्य दवा नियामकों के साथ सोमवार पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक मानकों को मजबूत किया जाना चाहिए कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी दवाएं ही बेची जाएं। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य दवा नियामकों से सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दवाएं केवल डाक्टरों की पर्ची या प्रेसक्रिप्शन के माध्यम से बेची जाएं ताकि मादक दवाओं को तस्करी या अन्य अवैध उपयोगों को रोका जा सके। उन्होंने 905 दवा निर्माण और परीक्षण फर्मों के जोखिम-आधारित निरीक्षण को पूरा करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य दवा नियामकों की सराहना की। निरीक्षणों के दौरान अब तक 694 कार्रवाई हुई है। यह बैठक भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा दर्द निवारक दवाओं टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के मद्देनजर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं को मुंबई स्थित फार्मा कंपनी एविओ फार्मास्यूटिकल्स ने पश्चिम अफ्रीकी देशों में निर्यात किया था, जिससे वहां संकट पैदा हो गया था। इन दवाओं का मादक पदार्थों के तौर पर नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। टेपेंटाडोल का उपयोग दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, वहीं कैरिसोप्रोडोल मांसपेशी रिलैक्सेंट है जो दर्द से राहत देता है।

No. TDB/15th FC/106/2024-25/1638 *Date- 24 /02/ 2025*

INVITATION FOR BIDS

The Block Development Officer, Tamulpur Development Block, Dist-Tamulpur, BTC, Assam invites bid affixing non-refundable Court fee Stamp of Rs.8.25(Rupees Eight and Twenty-Five Paisa) only from the approved and eligible contractor Class! (A, B, C), Class II or Class III category registered with Assam PWD (R&B)/Irrigation Deptt. for the following work under P&RD Deptt. under 15th FC (Tied Grant) for the year 2022-23 during 2024-25. Tender Box will be available for dropping tender in the Office of the Block Development Officer, Tamulpur Development Block from 25/02/2025 up to 2.00 PM on 20/03/2025 (if any holidays or Bandh falls then the subsequent day) and the tender box will be opened at the same day on 3.00 PM in same office.

Name of work	Tender value (In Rs.)	Time of Completion	Tender Cost & Earnest Money & Date ofTender
Construction of Community Toilet at Teteliguri Chowk.	Rs. 10,47,960.00	180 days fromthe date of issue of final work order.	1 .Tender cost @ 0.03% ofA/A amount to be pledgedby Bank draft in favour of Principal Secretary, BTC. 2. Eamest money @2% (Incase of ST/SC 1%) of estimated value to be pledged by demand draft/FDR in favour of B.D.O Tamulpur Development Block 3. Bidders are specifically requested to inspect the field and study the working condition before submitting their offer/bid.

Details NIT may be seen at Office of the B.D.O Tamulpur Development Block, Tamulpur, Dist- Tamulpur.

Sd/-
Block Development Officer,
Tamulpur Development Block, Tamulpur

IPR(BTC)-2023-24/1543

पृष्ठ एक का शेष

पूर्वोत्तर की भूमि से ...

हो गई है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में आयोजित *एडवांटेज असम : इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट-2.0* को संबोधित करते हुए पूरे पूर्वोत्तर के साथ-साथ भारत के विकास में असम के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। सम्मेलन में रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी, अडाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडाणी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के प्रमुख सज्जन जिंदल और टाटा ग्रुप के प्रमुख एन चंद्रेशखरन के साथ-साथ 60 देशों के राजदूत और राजनयिक उपस्थित थे। 2016 में भाजपा की सरकार बनने के बाद असम में तेज हुए आर्थिक प्रगति और आधारभूत संरचना की विकास की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले लगभग सात दशक में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुलों का निर्माण हुआ था। उनकी सरकार आने के बाद चार नए पुल बने हैं। इसके साथ-साथ सड़कों, पुलों, रेल और नए हवाई अड्डों के निर्माण से असम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में विकास की नई रफ्तार शुरू हुई है और असम इसकी अगुवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2018 में पहले निवेश सम्मेलन के समय असम की अर्थव्यवस्था 2.75 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस साल छह लाख करोड़ रुपए की हो गई है। एक साल बाद असम में होने वाले विधानसभा चुनावों के देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनने की स्थिति में असम के विकास की गति जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में पूरी दुनिया विकास को सशंकित हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के तेज आर्थिक विकास को लेकर सभी एकमत हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग में मिशन मोड में काम कर भारत लोकल सप्लाई चैन को मजबूत करने में जुटा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिवेटी और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत वैश्विक सप्लाई चैन में अहम हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ असम की नजदीकी को देखते हुए असम के पूरे क्षेत्र के विकास में गेटवे के रूप में काम करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंडिया-मिडिल इस्ट-यूरोप कोरिडोर के निर्माण से भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के 50-50 हजार करोड़ के निवेश के अलावा चंद्रेशखरन, सज्जन जिंदल और अनिल अग्रवाल ने भी असम में बड़े पैमाने पर निवेश का भरोसा दिया। उद्योगपतियों ने कभी हिंसाग्रस्त रहे असम में शांति, विकास और आधारभूत संरचना के बड़े पैमाने पर निर्माण की सराहना की।

असम में निवेश की...

विकास की शुरुआत की थी। उन्होंने संकेत दिया कि असम भविष्य में भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य बन सकता है। निवेशकों की भारी दिलचस्पी से यह साफ है कि असम भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विकास असम की सांस्कृतिक और पारंपरिक जड़ों को बनाए रखते हुए हो। एडवांटेज असम 2.0 के पहले दिन की समाप्ति तक, सरकार ने यह नहीं बताया कि कुल कितने निवेश प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लगी, लेकिन विभिन्न समूहों से प्राप्त निवेश आश्वासन 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। अब यह देखना होगा कि इन घोषणाओं का असम की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।

असम की अर्थव्यवस्था...

असम के आर्थिक इतिहास को रेखांकित करते हुए, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि कैसे स्वतंत्रता के बाद व्यापार मार्गों में व्यवधानों ने आर्थिक गिरावट को जन्म दिया। हालांकि, उन्होंने राज्य के पुनरुत्थान के लिए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि सबसे अशांत राज्य होने से असम अब सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक बन गया है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने से राज्यों में निवेश के अनुकूल नीतियां बन रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद सात व्यावसायिक शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है, जिसमें सभी राज्यों को एक साथ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य असम की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी।

ऐसा लगता है कि ...

लोगों द्वारा दिए जा रहे सहयोग का भी उल्लेख किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस व्यवसाय को समझता हूं। हम भारत में निजी क्षेत्र में तेल और गैस के एकमात्र उत्पादक हैं। यह बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है, लेकिन हमने तय किया है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जब आप तेल उत्पादन शुरू कर देते हैं, तो डाउनस्ट्रीम में बहुत से उद्यमी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि आज के समय में, असम के पास एक बहुत अच्छा बेसिन है, जिसमें बहुत सारे अन्वेषण अभियान हो सकते हैं... हम अपने दम पर तेल उत्पादन कर सकते हैं। असम ऐसा कर सकता है। शिखर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने असम की प्रगति के प्रति अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने असम की रणनीतिक स्थिति, निवेश समर्थक नीतियों और बढ़ते बुनियादी ढांचे को भारत के विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उजागर किया। असम को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बताते हुए उन्होंने राज्य के दीर्घकालिक, सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अग्रवाल ने कहा कि असम में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और इसमें दुनिया का मेगा बेसिन बनने की क्षमता है। हम असम के सतत विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ, हम असम से प्रतिदिन 100,000 बैरल तेल और गैस का उत्पादन करेंगे - जिससे यह एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन केंद्र बन जाएगा, साथ ही 1 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

असम में 50,000...

और हम अगले पांच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अंबानी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में यह राशि लगाई जाएगी, उनमें हरित व परमाणु ऊर्जा, खाद्य व गैर-खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला और रिलायंस के खुदरा स्टोर का विस्तार शामिल है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर के बारे में अंबानी ने कहा किआपने (मोदी) असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत के विकास के नक्शे के केंद्र में ला दिया है। आपने खुद इस क्षेत्र का 70 से अधिक बार दौरा किया है - अतीत में किसी भी अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक। मुंबई में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ अपनी बैठक को याद करते हुए अंबानी ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों ने उन्हें आश्वस्त किया कि असम का भविष्य साहसिक और असाधारण है। उन्होंने आगे कहा किमैंने खुद से कहा कि जब असम अपने लिए इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, तो उद्योग में रिलायंस कैसे पीछे रह सकती है? असम में भविष्य के निवेश के पांच क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि रिलायंस की पहली प्राथमिकता असम को तकनीक और एआई के लिहाज से तैयार करना है। अंबानी ने कहा कि कंपनी की दूसरी प्राथमिकता असम को परमाणु ऊर्जा सहित स्वच्छ और हरित ऊर्जा का केंद्र बनाना है। रिलायंस समूह की तीसरी निवेश प्राथमिकता असम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ता उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने में मदद करना है। चौथी प्राथमिकता के रूप में रिलायंस राज्य में अपने खुदरा कारोबार का विस्तार करेगी। उन्होंने कहा किहमारी पांचवीं प्राथमिकता असम में उच्च श्रेणी के होटल और आतिथ्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। रिलायंस असम में एक शानदार सात सितारा होटल बनाएगी।

जीएमसी एकता और ...

कहा कि भारत सरकार के साथ-साथ असम सरकार भी जीएमसी की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार जीएमसी की पहल के साथ तालमेल बैठाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में समान विकास लाने के लिए विभिन्न संभावनाओं की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है, जो असम की क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जीएमसी की व्यापक दृष्टि का समर्थन करता है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार की स्वीकृति मिलने पर असम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सेज, जीएमसी की परिकल्पना के अनुरूप एक टाउनशिप के निर्माण में सहायक होगा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, कोकराझाड़-गेलगेलफू रेल संपर्क और गेलगेलफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) के आसपास सड़क अवसंरचना के विकास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिससे मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर भूटान सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री योंतेन फुंतशो ने अपने संबोधन में हरित ऊर्जा, कृषि नवाचार और आर्थिक स्थिरता को लेकर भूटान की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने नवाचार, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत-भूटान सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम ने अवसंरचना, व्यापार और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे भविष्य में भूटान के लिए भी कई अवसर सृजित होंगे। इस सत्र में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, भूटान सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री योंतेन फुंतशो, विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्घेरीटा, बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोड़ो, असम सरकार के मंत्री यूजी ब्रह्म, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के सीईओ एवं एमडी डॉ. प्रवीर सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अशांत से सबसे ...

से हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 मिलियन मीट्रिक टन तक विस्तारित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने असम के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक 2,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2013 में 29 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 68.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम बिजनेस और निवेशकों के लिए असम के तेजी से बढ़ते औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉ. एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्वानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी सहित उद्योगपति भी मौजूद हैं।

पूसीरे ने बेहतर संरक्षा के लिए बुनियादी संरचनाओं की निगरानी बढ़ाई

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) कुशल और अधिक सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्नत प्रौद्योगिकी को निरंतर अपनाते हुए, पूसीरे अपने बुनियादी संरचनाओं को उन्नत करने और बरकरार रखने का प्रयास करता है। दक्षता और संरक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए, जोन के अधीन कई सेक्शनों में सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य संरक्षा उपकरणों में कई उन्नयन और प्रतिस्थापन किए गए है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज एक बयान में बताया है कि चालू वर्ष के जनवरी माह में, पूसीरे ने अलीपुरद्वार और रंगिया मंडलों के दो स्थानों पर क्लैंप-टाइप लॉकिंग के साथ थिक वेब स्विच प्वाइंट मशीनें लगाई। पूसीरे ने कटिहार में 20 प्वाइंट मशीन और अलीपुरद्वार मंडल में 11 प्वाइंट मशीनों को प्रतिस्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप पटरी से उतरने की संभावना को कम करने और सुरक्षित यात्री एवं माल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी संरचना में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए कटिहार, लामडिंग, रंगिया और तिनसुकिया मंडलों के पांच समपार फाटकों पर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर प्रतिस्थापन किए गए हैं। रंगिया, लामडिंग और अलीपुरद्वार मंडलों में, कई स्टेशनों पर 17.712 किमी नई सिग्नलिंग केबल लगाए गए है। रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए संरक्षा उपायों के तहत, सात स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम चालू किए गए है। पूसीरे के अलीपुरद्वार, रंगिया और लामडिंग मंडलों के विभिन्न स्थानों के 19 समपार फाटकों पर सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्टिंग की गई है। पूसीरे के चार मंडलों में विभिन्न क्षमताओं के कुल 388 सिग्नलिंग बैटरियों को प्रतिस्थापित किया गया, जिससे संरक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ी है। उन्नत संचार प्रणालियां चालक और संचालक दोनों को वास्तविक समय के दृश्य की सूचना प्रदान करती हैं, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होता है, समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित होता है और रेलवे की समग्र संरक्षा को बढ़ावा मिलता है। रेलवे प्रणाली की बुनियादी संरचना के अपग्रेडेशन सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। स्थापित बुनियादी संरचना की विश्वसनीयता और अनुरक्षण सीधे तौर पर रेलवे परिचालन की दक्षता तथा क्षमता को प्रभावित करती है। पूसीरे अपने सभी ग्राहकों के लिए उत्तम, समयनिष्ठ और सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करने को प्रतिबद्ध है।

पंजाब में ड्रग तस्करी के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी सोमवार की देररात नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। मंगलवार को पंजाब विधानसभा में दूसरे दिन का सत्र शुरू होने से पहले पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस ने एक वीडियो जारी कर इस मामले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस ने तलवंडी इलाके में यह कार्रवाई की गई है। तलवंडी के ड्रग माफिया सोनू के घर को गिरा दिया गया है। सोनू तीन साल से ड्रग तस्करी में लिप्त था और उसके खिलाफ पंजाब के विभिन्न थानों में छह एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि उक्त संपत्ति ड्रग्स बेचकर बनाई गई है। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सरकार ने इसे नया नाम दिया है। पंजाब पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि वॉर ऑन ड्रग्स के तहत पंजाब सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है।

कार्बी आंगलांग और बाक्सा जिले में एडवांटेज असम 2.0 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

कार्बी आंग्लांग। कार्बी आंग्लांग जिले के आयुक्त नेरोला फंगछोपी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में एडवांटेज असम 2.0 के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्बी आंग्लांग जिले के कुल 96 उद्यमियों ने आज यहां कृषि, हस्त तांत व वस्त्र शिल्प के साथ उद्योग और पर्यटन विभाग के विभिन्न योजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडवांटेज असम के तहत सभी जिलों में 5 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा सकेगा। कार्बी आंग्लांग जिला कोयला और अन्य खनिजों से बहुत समृद्ध है, इसके अलावा विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिए पर्याप्त पर्यटन विभाग के मांग है। कार्बी आंग्लांग में कई अनछुए पर्यटन स्थल भी हैं, यदि उनका अच्छी तरह से प्रचार-प्रसार और विकास किया जाए तो कार्बी आंग्लांग जिले के लोगों के लिए आय के अवसर खुलेंगे। डिफू से सोहन प्रसाद महतो के साथ कैमरे पर प्रदीप मजूमदार, दूसरी ओर **बाक्सा** जिला आयुक्त गौतम दास ने मुशालपुर में डीसी कार्यालय से एडवांटेज असम 2.0 समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया, उनके साथ डीएओ दुलाल दास और अन्य विभागाध्यक्ष और अधिकारी भी थे। कार्यक्रम में बोलते हुए, डीसी गौतम दास ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिला स्तर पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन निवेशकों को पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करेंगे, मौजूदा नीतियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति, पंजीकरण, अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा प्रदान करेंगे। ये समझौते बाक्सा में परियोजनाओं की समय पर स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे जिले के आर्थिक विकास में और तेजी आएगी और असम के समग्र औद्योगिक विकास में योगदान मिलेगा। असम सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन राज्य की सबसे बड़ी निवेश प्रोत्साहन और सुविधा पहल है। इसका उद्देश्य असम के भू-रणनीतिक लाभों और विशाल आर्थिक क्षमता को उजागर करना तथा इसे क्षेत्र में एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की सराहना की

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी, असम प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन में दिए गए प्रेरणादायक और दूरदर्शी संबोधन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक विशेषज्ञों का बढ़ता विश्वास स्पष्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और पूर्वोत्तर को व्यापार, उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रमुख केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति उनकी गहरी निष्ठा प्रदर्शित होती है। उनके द्वारा निवेश के अवसरों को गति देने और असम की आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ करने पर दिया गया जोर इस क्षेत्र के समावेशी विकास के प्रति सरकार के अटूट संकल्प को दर्शाता है। भाजपा असम प्रदेश को पूर्ण विश्वास है कि यह शिखर सम्मेलन असम में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार के नए द्वार खोलेगा, जिससे राज्य भारत की आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के कुशल नेतृत्व में असम विकास के एक अभूतपूर्व युग का साक्षी बन रहा है, जिसमें दीर्घकालिक समृद्धि की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भाजपा असम प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनके निरंतर समर्थन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिससे असम की प्रगति और भारत की आर्थिक यात्रा में उसकी सशक्त भूमिका सुनिश्चित हो रही है। भाजपा असम प्रदेश प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है और *विकसित भारत* की यात्रा में असम को एक केंद्रीय भूमिका निभाने हेतु तत्पर है।

दो महिला समेत तीन ड्रग्स तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की दिसपुर पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी मामले में शामिल तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिसमें दो महिला तस्कर भी शामिल हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के खानकाह रोड के दक्षिण गांव इलाके में में चलाए गए अभियान के दौरान तीन ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें दो महिला तस्कर शामिल हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सद्दाम अली, मुश्फूल बेगम और सलमा सुल्तान के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 प्लास्टिक की छोटी-छोटी सीसी में भरकर रख गए 14.67 ग्राम हेरोइन, एक ऑल्टो कार (एएस-01एससी-3931), एक बिना नंबर प्लेट की एन-16 बाइक, दो मोबाइल फोन के अलावा नगद 11 हजार रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस इस मामले में एनडीपीएस धारा के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तीनों तस्करों से सघन पूछताछ कर रही है।

रंगिया : महाशिवरात्रि पर मिलनपुर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन

रंगिया (विभास)। महाशिवरात्रि के अवसर पर रंगिया के मिलनपुर स्थित नागेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मंदिर प्रांगण में महा रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि महारुद्र यज्ञ नेपाल में पशुपति मंदिर के ब्राह्मणों के माध्यम से कराया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ मंगलवार को धार्मिक शोभायात्रा एवं कलश यात्रा के साथ किया गया। मंदिर प्रांगण से निकली यह कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। जिसका शुभारंभ रंगिया थाना प्रभारी नवजीत नाथ द्वारा किया गया। आयोजन समिति द्वारा मंदिर के इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में सभी भक्तों की उपस्थिति एवं सहयोगिता की कामना की गई है।

असम बायो ई3 नीति लागू करने वाला पहला राज्य : मंत्री केशव महंत

गुवाहाटी (हिंस)। असम में बायो-टेक्नोलॉजी उद्योग में बायो-मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब और बायो-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने जा रहा है। असम के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्री केशव महंत ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की। खानापाड़ा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मैदान में आयोजित निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के दौरान बायो-टेक्नोलॉजी *बायो-मैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्रीज- असम के रोडमैप के लिए बायो ई3 नीति का लाभ उठाना* पर विशेष सत्र में अपना स्वागत भाषण देते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। मंत्री महंत ने जोर देकर कहा कि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ असम हरित अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि असम सरकार अब विकास की दिशा में राज्य के रोडमैप के रूप में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम राज्य में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही असम में बायो ई3 नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गतिशील मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के विजन के साथ, राज्य ने बायो ई3 नीति की गतिविधियों के समन्वय के लिए इसी बीच एक बायो ई3 सेल को अधिसूचित कर दिया है। एक जीवंत और टिकाऊ असम के लिए उद्यमियों और स्टार्ट-अप को असम के हरित विकास पथों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए, राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मौजूदा असम जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-23, असम स्टार्ट-अप नीति और राज्य औद्योगिक नीति निवेशकों और स्टार्ट-अप के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि असम सरकार राज्य में जैव-विनिर्माण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने कहा कि हमने जैव-विविधता आधारित नवाचार, भविष्य के लिए उपयुक्त ताजा पानी, खाद्य जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सुगंध एवं सुगंध जैव-प्रौद्योगिकी जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। हमारी सरकार इन प्रमुख क्षेत्रों

में नवाचार, अनुसंधान, स्टार्ट-अप और उद्योगों के लिए हर संभव सहायता देने में प्रसन्न होगी। सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अलका शर्मा ने बायो ई3 नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए असम की सराहना की। अपने मुख्य भाषण और उद्घाटन भाषण में डॉ. शर्मा ने कहा कि एक बार बायो ई3 सेल की स्थापना हो जाने के बाद, राज्य में एक संरचित मार्ग और पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिससे इस जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप, शिक्षाविद और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। इस सत्र में बायोनेस्ट, आईआईटी गुवाहाटी के सीईओ डॉ. स्वप्निल सिन्हा द्वारा संचालित एक विशेषज्ञ पैनल चर्चा भी हुई, जिन्होंने सत्र के लिए संदर्भ निर्धारित किया और प्रतिष्ठित पैनलिस्ट डॉ. मनीष दीवान, भारत सरकार के बीआईआरएसी के प्रमुख - बायो-फाउंड्री, राजीव गांधी, संस्थापक, सीईओ और एमडी, हेस्टर बायो-साइंसेज लिमिटेड, कृष्णन जी.एस., एबीएलई के अध्यक्ष और फर्मबॉक्स के संस्थापक सुब्रमणि रामचंद्रप्पा के साथ एक आकर्षक बातचीत की सुविधा प्रदान की। पैनल चर्चा के दौरान, हेस्टर बायो-साइंसेज लिमिटेड के संस्थापक राजीब गांधी ने कहा कि असम का स्वच्छ पर्यावरण और अच्छी जल गुणवत्ता राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी विकास के लिए आदर्श स्थान है। फर्मबॉक्स के संस्थापक रामचंद्रप्पा ने भी उम्मीद जताई कि असम की बायो ई3 नीति निकट भविष्य में असम में बायोटेक्नोलॉजी हब को बढ़ावा देगी। फर्मबॉक्स के संस्थापक का समर्थन करते हुए, एबीएलई के अध्यक्ष कृष्णन ने भी बायो ई3 नीति पर संतोष व्यक्त किया। राज्य सरकार के साथ-साथ डीबीटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि असम की बायो ई3 नीति भविष्य में और अधिक स्टार्ट-अप को सफल होने में मदद करेगी। दुनिया भर में बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देते हुए, बीआईआरएसी के बायो-फाउंड्री के प्रमुख मनीष दीवान ने कहा कि जीडीपी की तुलना अब वैश्विक स्तर पर बायो-इकोनॉमी के संदर्भ में की जाती है। बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र पर विषयगत सत्र से पहले, आज 15 संगठनों के साथ 95 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 13 वित्तीय और 2 तकनीकी समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

24वीं वाहिनी एसएसबी का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर संपन्न

कामरूप (हिंस)। कामरूप (ग्रामीण) जिलांतर्गत रंगिया स्थित 24वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट दीपक सिंह के दिशा-निर्देश पर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रम (पूर्वोतर) के तहत कराये गए 15 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। शिविर का शुभारंभ गत 04 फरवरी को किया गया था। यह प्रशिक्षण शिविर देश के सीमा क्षेत्र के कुमारीकाटा स्थित *खादी ग्राम उद्योग विद्यालय* के माध्यम से बीते 4 फरवरी से कावली स्थित *खादी ग्राम उद्योग विद्यालय* में शुरू किया गया था। इस प्रशिक्षण में कुल 30 (पुरुष-21, एवं 9 महिलाएं) प्रतिभागियों ने भाग लिया था। मुख्य अतिथि एसएसबी की 24वीं वाहिनी के उप कमांडेंट अश्वनी कुमार शुक्ला ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र के युवाओं एवं ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन की जानकारी देना रहा, जिससे वह अपने लिए रोजगार के रूप में भी उपयोग कर सके एवं इसे व्यवसायिक रूप भी दे सके। उप कमांडेंट शुक्ला ने कहा कि मधुमख्खी पालन वर्तमान में अत्यंत लाभकारी विषय है इसकी मांग पूरे विश्व भर में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 30 पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लिया। 24वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपने कार्यक्षेत्र के नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर इस प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करते रहे, जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से समर्थ बनाया जा सके एवं हमारा देश निरंतर रूप आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमरा ध्येय सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व है। हम सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे एवं अपना हर संभव प्रयास करेंगें। कार्यक्रम में उपस्थित सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिक काफी उत्साहित दिखे एवं उन्होने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान 24वीं वाहिनी के अन्य अधिकारीगण एवं बल के कर्मी भी उपस्थित रहे।

यौन उत्पीड़न मामले में वृद्ध व्यक्ति गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की लताशील पुलिस ने नाबालिक लड़की से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक वृद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि थाने में दर्ज कराई गयी एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, लताशिल थाने की सीजीपीडी टीम ने यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शंकर बासफोर (62) को गिरफ्तार किया। पीड़िता का जीएमसीएच में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। घटना के संबंध में बाल कल्याण समिति एवं एसएमआरएक्स को सूचित कर दिया गया है।

सेंगा में भयावह सड़क हादसे में एक की मौत, दो घायल

बरपेटा (हिंस)। बरपेटा के निज सेंगा में बीती रात एक भयावह सड़क दुर्घटना में एक कार (एएस-01डीटी-6350) नियंत्रण खोने के बाद बिजली के खंभे से टकरा गया। वैगनआर कार बरपेटा से सेंगा की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान कुकर पार गांव के सानोअर काजी के रूप में हुई है। घायलों की शिनाख्त फरहाद अली और मृदुल अली (दोनों कुकर पार गांव के निवासी) बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए बरपेटा फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर पहुंची ताराबारी पुलिस मामले की जांच जारी रखें हुए है।

असम एडवांटेज समिट में बीएसएनएल के सीएमडी का संबोधन

गुवाहाटी। बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री ए रॉबर्ट जे. रवि ने असम एडवांटेज 2.0 समिट को संबोधित किया और *आई-वे टू विकसित असम* विषय पर असम के डिजिटल सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के लिए अपनी दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कनेक्टिविटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के माध्यम से राज्य के डिजिटल परिवर्तन में बीएसएनएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मुख्य फोकस क्षेत्र : नागरिकों को सशक्त बनाना-सभी के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना, मेटावर्स-आधारित नागरिक सेवा केंद्र, जहां नागरिक अपनी भाषा में एआई संचालित डिजिटल अवतारों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकें। भूमि पट्टा, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों की त्वरित डिजिटल प्रोसेसिंग। एक-टच ऑथेंटिकेशन के जरिए कल्याणकारी योजनाओं तक त्वरित पहुंच। उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना-उद्यमों एवं एमएसएमई को सशक्त करना इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग। 5ल कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क विकसित कर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल उद्यमों को बढ़ावा देना। ब्लॉकचेन-आधारित आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से व्यापार और निर्यात में पारदर्शिता बढ़ाना। स्मार्ट एवं डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना एआई-संचालित गवर्नेंस मॉडल, जिससे शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सके। डिजिटल ट्विन नेटवर्क, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। ब्लॉकचेन-आधारित डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क शासन की दक्षता बढ़ाने के लिए। **असम के लिए बीएसएनएल की प्रमुख डिजिटल पहल :** भारतनेट विस्तार: 26, 000 गांवों और 2, 265 ग्राम पंचायतों को 15, 575 किमी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। 5 प्रतिशत और प्राइवेट नेटवर्क : औद्योगिक क्षेत्रों जैसे तेल, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स में 5 प्रतिशत नेटवर्क विकसित करने के लिए एमट्रॉन के साथ साझेदारी। स्मार्ट सिटी एवं आईओटी समाधान: शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एआई-संचालित ट्रैफिक सिस्टम, आईओटी-आधारित ग्रिड और वाई-फाई हॉटस्पॉट। *विकसित असम* की ओर एक दृष्टि श्री रवि ने स्मार्ट ग्रिड फ्रेमवर्क को असम की डिजिटल रीढ़ बताते हुए चार मुख्य घटकों को परिभाषित किया। सिटिजन ग्रिड : हर घर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। इकोनॉमिक ग्रिड : एमएसएमई और औद्योगिक विकास को सशक्त करना। प्रोसेस ग्रिड: एआई-आधारित स्वचालित शासन प्रणाली। कनेक्टिविटी ग्रिड: राज्य में हाई-स्पीड और विश्वसनीय नेटवर्क उपलब्ध कराना। अपने संबोधन के अंत में, उन्होंने असम को भारत में डिजिटल परिवर्तन का एक आदर्श मॉडल बनाने के प्रति बीएसएनएल की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिससे यह राज्य तकनीकी रूप से उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।

पूर्वांचल जाट समाज ने जाट भवन में लगाया विशाल रक्तदान शिविर

गुवाहाटडी। नगर के गोरचुक स्थित जाट भवन में 23 फरवरी रविवार को पूर्वांचल जाट समाज द्वारा मानवता की सेवा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि दीपांकर बरुवा प्रभारी ब्लड बैंक गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रक्तदान शिविर के संयोजक व समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के आर चौधरी, समाज के अध्यक्ष गणेश चौधरी, कोषाध्यक्ष श्रीचंद ढाका, मोहनलाल बिजारणिया, सेवाराम शिवराण, बिजेंद्र मातवा के दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। रक्तदान महादान को आत्मसात करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष गणेश चौधरी ने रक्तदान कर कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। उसके बाद समाज बंधुओं के साथ साथ सर्वसमाज के लोगों ने भी शिलांग, बर्निहाट व अन्य दूर-दूर स्थानों से आकर इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और पूरे जोश और उत्साह के साथ रक्तदान किया। सुबह 10 से शुरू हुआ ये आयोजन शाम 4 बजे तक चला जिसमे कुल 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की और से 10 सदस्यीय टीम ने 4 बेड वाली बड़ी गाड़ी यानी मिनी ब्लड बैंक रक्त संग्रह के लिए उपलब्ध करवाया गया। समाज द्वारा जाट भवन में मेडिकल स्टाफ और रक्तदाताओं के बैठने लिए समुचित व्यवस्था की गई। इसके आलावा रक्तदाताओं के लिए फल, ज्यूस, निंबू पेय, फ्रूटी, चाय,

बिस्किट आदि की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष गणेश चौधरी, शिविर संयोजक व कार्यकारी अध्यक्ष श्री केआर चौधरी, महासचिव रामस्वरूप ढाका, कोषाध्यक्ष श्रीचंद ढाका, धनपत भूकर, रामकुमार फगेड़िया, मोहनलाल बिजारणिया, सेवाराम शिवराण, बिजेंद्र मातवा, अमरचंद नागा, अनिल संधू, भंवरलाल पुनिया सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से छोटे शहरों को मिला विकसित होने का मौका : मुख्यमंत्री

- समिट में अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर सेशन शुरू
- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी समिट में शामिल होने पहुंचे

भोपाल, (हि.स.)। नगर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आज अंतिम दिन है। मंगलवार को अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर मुख्य हॉल में शुरू हुए सेशन ाको मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में यह भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अफसरों का कहना था कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल नहीं बल्कि इंदौर में होनी चाहिए तो मैंने कहा कि इंदौर को दिल्ली और बड़े शहरों की तरह विकसित करना है। भोपाल और अन्य शहरों को इंदौर की तरह विकसित करना है, इसलिए भोपाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जाएगी। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट करेंगे।

अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता: विजयवर्गीय

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता है। वर्ष 2047 तक प्रदेश की जनसंख्या 7 प्रतिशत बढ़ जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 2 महीने में 18 नई पॉलिसी बनाई हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट की भारी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मंत्री के रूप में मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। तय कार्यक्रम के तहत समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। इससे पहले केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी समिट में पहुंचे हैं।

सेशन में शामिल होने से पहले खट्टर ने डिजिटल हैरिटेज वॉल देखी। बाग प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक (छापा) लगाया। सेशन हॉल में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की महापौर मालती राय मौजूद हैं। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इसमें अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत देश-विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे। आज शाम को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और इन्वेस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के पहले दिन सोमवार को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए। इससे प्रदेश में 13 लाख 43 हजार 468 रोजगार मिलेंगे। अडाणी ग्रुप 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल में 60 हजार करोड़ का निवेश करेगी। वहीं, हिंडाल्को ग्रुप सिंगरौली में 15 हजार करोड़ का प्लांट लगाने जा रहा है। अवादा ग्रुप ने 50 हजार करोड़ से 8000 मेगावाट का सोलर विंड पावर और बैटरी प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जताई। वहीं, सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में ढाई हजार करोड़ का निवेश करेगा।

रक्षा मंत्री ने भारत मंडपम में तटरक्षक बल के कर्मियों को दिए राष्ट्रपति पदक

- समुद्री हितों की रक्षा करने में आईसीजी की निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण : राजनाथ

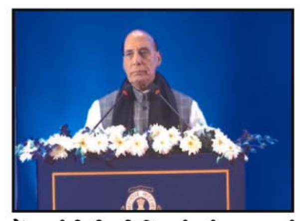

नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के कर्मियों को वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए, जो अक्सर चुनौतीपूर्ण और चरम स्थितियों में दिए जाते हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने सेरेमोनियल गार्ड का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने आईसीजी कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (पीटीएम) और तटरक्षक पदक (टीएम) उनकी अनुकरणीय सेवा, वीरता के कार्यों और कर्तव्य के प्रति निःस्वार्थ समर्पण के सम्मान में प्रदान किए। समारोह में कुल 32 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए 06 पीटीएम, वीरता के लिए 11 टीएम और सराहनीय सेवा के लिए 15 टीएम शामिल हैं। ये पुरस्कार आईसीजी कर्मियों के अटूट साहस, वीरता और प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं, जिनका योगदान भारत की विशाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आईसीजी के कमांडर अमित उनियाल ने बताया कि इन प्रतिष्ठित पदकों का प्रदान किया जाना न केवल पुरस्कार विजेताओं की व्यक्तिगत वीरता को मान्यता देता है, बल्कि पूरे भारतीय तटरक्षक बल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला भी है। यह देश के समुद्री हितों की रक्षा करने में आईसीजी की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। खासकर समुद्र में लगातार विकसित हो रही चुनौतियों के बीच बहादुर पुरुषों और महिलाओं की मान्यता को समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उत्कृष्टता के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। समारोह के समापन अवसर पर आईसीजी परंपराओं के अनुरूप पुरस्कार विजेताओं के परिवारों के साथ रक्षा मंत्री और महानिदेशक भारतीय तटरक्षक ने बातचीत की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने न केवल अनुकरणीय व्यक्तियों को सम्मानित किया, बल्कि राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के अपने अथक प्रयास में भारतीय तटरक्षक के गौरव और समर्पण को भी मजबूत किया है। आईसीजी के 18वें भारतीय तटरक्षक अलंकरण समारोह में रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आईसीजी के वरिष्ठ अधिकारी और पुरस्कार विजेताओं के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा)

01. एडीजी डोनी माइकल
02. एडीजी आनंद प्रकाश बडोला
03. आईजी मनीष विशाल पाठक
04. आईजी भीष्म शर्मा
05. आईजी मनोज वसंत बादकर
06. आईजी दिनेश राजपुत्रान

तटरक्षक पदक (वीरता)

01. कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाइक
02. कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी
03. कमांडेंट सुमित धीमान
04. कमांडेंट अनुराग शुक्ला
05. लेट कमांडेंट (जेजी) सौरभ
06. कमांडेंट (जेजी) विकास नारंग
07. डिप्टी कमांडेंट आकिल पठान
08. अर्ध प्रगति कुमार
09. ऋषि, पी/एनवीके(आर)
10. सुल्तान सिंह
11. मोहित कुमार यादव

तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा)

01. डीआईजी अनिल कुमार परायिल
02. डीआईजी हिमांशु नौटियाल
03. डीआईजी जमाल ताहा
04. डीआईजी बालकृष्णन मुरुगन
05. डीआईजी प्रशांत कुमार शर्मा
06. डीआईजी पंकज वर्मा
07. डीआईजी मनोज भाटिया
08. डीआईजी केआर दीपक कुमार
09. कमांडेंट सुंदररमन प्रेम कुमार
10. श्रीप्रकाश, पीएसई (ईआर)
11. ए मणिकंदन, पीएसई (आर)
12. गिरीश कुमार वर्मा
13. संत लाल
14. देवब्रत कुमार मिश्रा
15. दीपक रॉय

एलजी के अभिभाषण के दौरान शोर-शराबा करने पर आप पार्टी के 21 विधायक तीन दिन के लिए निलंबित

अजय त्यागी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के बीच गतिरोध पैदा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। बताया गया है कि यह निलंबन दो हिस्सों में किया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की नेता आतिशी सहित गोपाल राय और अन्य 12 विधायकों को एक दिन के लिए एलजी के संबोधन के दौरान नारेबाजी करने पर सदन से बाहर कर दिया।

इसमें वीर सिंह धिंगान, मुकेश अहलावत, चौधरी जुबैर अहमद, अनिल झा, विशेष रवि और जरनैल सिंह व अन्य शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के अपना अभिभाषण शुरू करते ही विपक्षी आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे जय भीम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने मार्शल बुलाकर हंगामा करने वाले विधायकों को बाहर करने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है और सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं, जो 27 फरवरी को जारी रहेगी और फिर इसे आगे की कार्रवाई के लिए लोक लेखा समिति को भेजा जाएगा। सीएजी रिपोर्ट के अन्य खंड भी भविष्य में सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदन में हुए हंगामे के बाद आआपा विधायकों के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने एलजी के अभिभाषण के दौरान बहुत ही असंवैधानिक तरीके से व्यवहार किया। सदन की गरिमा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका (आआपा के सदस्यों का) व्यवहार निंदनीय है। इसलिए उनका निलंबन तीन बैठकों (25, 27 और 28 फरवरी) तक वैध है। निलंबित आआपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में अंबेडकर की तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और "जय भीम" के नारे लगाए।

डीएमआरसी ने फेज-4 का निर्माण पूरा किया

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने चौथे चरण का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। डीएमआरसी के अनुसार तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर के छतरपुर मंदिर और इग्नू स्टेशन के बीच एक भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। इग्नू स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) की सफल ब्रेकथ्रू प्रक्रिया में मंगलवार को उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आनंद मोहन बजाज, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रमोद कुमार, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने मंगलवार सुबह इग्नू स्टेशन पर, 1475.00 मी. लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया। यह कार्य 97 मीटर लंबी विशाल टीबीएम का उपयोग करके संपन्न किया गया। डीएमआरसी के अनुसार इस खंड में अप और डाउन मूवमेंट के लिए दो समानांतर गोलाकार सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी समानांतर सुरंग का ब्रेकथ्रू मार्च 2025 में निर्धारित है। यह नई सुरंग औसतन 26.0 मीटर की गहराई पर बनाई गई है (न्यूनतम गहराई 15.0 मी. और अधिकतम 36 मी.), जिससे यह दिल्ली मेट्रो की सबसे गहरी सुरंगों में से एक बन गई है। हौज खास स्थित मैजेंटा लाइन की सुरंग लगभग 30 मीटर की गहराई पर बनी है। इस सुरंग में 1048 रिंग्स लगाए गए हैं, जिनका आंतरिक व्यास 5.8 मीटर है। इस सुरंग का निर्माण ईपीबीएम (अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मेथड) तकनीक का उपयोग करके किया गया है। जिसमें प्रीकास्ट टनल रिंग्स की कंक्रीट लाइनिंग की गई है। इन टनल रिंग्स को मुंडका में स्थापित एक पूरी तरह से स्वचालित कास्टिंग यार्ड में तैयार किया गया था। इसमें कंक्रीट सेगमेंट को शीघ्र मजबूती प्रदान करने के लिए स्टीम क्योरिंग सिस्टम के माध्यम का उपयोग किया गया। डीएमआरसी ने आगे बताया कि इस सुरंग की बोरिंग प्रक्रिया चार दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी, जिसमें तीव्र ढलान और अभ्रक तथा कठोर चट्टान जैसी विविध भूगर्भीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस कारण स्क्रू ऑगर क्षतिग्रस्त हो गया और इसे सुरंग निर्माण के दौरान बदला गया। मौजूदा वायाडक्ट और आसपास के निर्मित ढांचों के नीचे सुरंग निर्माण के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए गए। इसके अलावा पास की संरचनाओं पर उच्च संवेदनशीलता वाले उपकरण लगाए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भूमि धंसाव न हो। अब तक स्वीकृत चौथे चरण के कार्य के तहत कुल 40.109 कि.मी. भूमिगत लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के तहत 19.343 कि.मी. भूमिगत सेक्शन शामिल है।

सोमनाथ मंदिर को मिला ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप का प्रमाणपत्र

गांधीनगर/अहमदाबाद, (हि.स.)। सोमनाथ मंदिर को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अपनाने के लिए ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप प्रमाणपत्र दिया गया। वर्तमान में गुजरात में कुल 47 मंदिरों को यह प्रमाणपत्र मिला है। राज्य के खाद्य आयुक्त डॉ. एचजी कोशिया ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उनके जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। गुजरात के सोमनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर देश के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को स्वच्छ और सुरक्षित प्रसाद मिले इसके लिए सोमनाथ मंदिर का थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी ने ऑडिट किया गया है और इसे ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप सर्टिफिकेट दिया गया है। गुजरात सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य के मंदिरों में भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद उच्च गुणवत्ता वाला हो। उल्लेखनीय है कि ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप (पीओडब्ल्यू) एफएसएसएआई की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पूजा स्थलों (पीओडब्ल्यू) को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य पूजा स्थलों में प्रसाद, लंगर आदि में परोसे जाने वाले भोजन में अनियमितताओं को रोकना और उनके बारे में जागरुकता पैदा करना है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक के तहत नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए मंदिरों आदि में एफएसएसएआई के पैनलबद्ध ऑडिट एजेंसी ऑडिट करती है। उसके बाद प्रसाद से जुड़े व्यक्तियों को एफओएसटीएसी का प्रशिक्षण देने के बाद फिर ऑडिट किया जाता है। इसके बाद भोजन की गुणवत्ता चेक करने के बाद ही ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप प्रमाणपत्र दिया जाता है।

सिख विरोधी दंगा : बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद

नई दिल्ली, (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 12 फरवरी को ही दोषी करार दिया था। आज फैसला आने के पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट के सामने सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की। यह मामला 01 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राजनगर इलाका स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला किया था। शिकायतकताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया। भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 395, 397, 302, 307, 436 और 440 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने लगाया उप्र में शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप, न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। बाराबंकी से पार्टी सांसद तनुज पूनिया ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता में कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का एक घोटाला सामने आया है। इस भर्ती में 18 हजार 500 आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्ती की जानी थी लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। इन आरक्षित सीटों में से बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने इसे संविधान में प्रदत्त आरक्षण पर हमला और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दलित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का काम कर रही है। इस फैसले के खिलाफ जिन छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, उन्हें भी सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया। हमारे नेता लगातार सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। कांग्रेस हमेशा वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस भर्ती घोटाले में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है।

उपराज्यपाल अभिभाषण: भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकुशल शासन देगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में बनी दिल्ली सरकार के 10 सूत्री एजेंडे को सामने रखा। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर ध्यान देते हुए दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकुशल सरकार देगी। उपराज्यपाल ने 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार को अपने अभिभाषण में नई भाजपा सरकार का रोड मैप पेश किया। उन्होंने 10 सूत्री एजेंडे के बारे में बताया। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, महिलाओं का सशक्तीकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ पानी और अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण और सस्ती आवास सुविधायें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नीति दस्तावेज के रूप में विकसित दिल्ली के संकल्प को बनाएगी और आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करें। उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार इस बात पर विश्वास रखती है कि लगातार गतिरोध की राजनीति करने और एक दूसरे पर आरोप लगाने से पिछले 10 साल से दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस तरह की स्थिति को पूरी तरह से छोड़ा जाएगा। उनकी सरकार समन्वय के साथ सहयोग करते हुए केंद्र के साथ काम करेगी। अन्य राज्यों की तरह सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में काम करेगी।

दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश, आप पार्टी सरकार की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान

अजय त्यागी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दिल्ली सरकार को अपनी 2021-22 की आबकारी नीति में खामियों के कारण 2,026.91 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय झटका लगा है। इसमें दिल्ली आबकारी शराब नीति में कथित अनियमितताओं सहित पिछली आआपा सरकार के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और दिल्ली में विदेशी शराब के विनियमन और आपूर्ति की जांच के लिए 2017-18 से 2021-22 तक चार वर्षों की अवधि को कवर करते हुए दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। वर्ष 2017-21 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्षों में लाइसेंस प्रदान करने में उल्लंघन करने के साथ ही आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, शराब की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण, राजस्व रिसाव की समय पर पहचान और रोकथाम व शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कमजोर नियामक कार्यप्रणाली, दिल्ली आबकारी अधिनियम अथवा नियमों के उल्लंघन के मामलों में साक्ष्य संग्रह और पुष्टि में कठोरता की कमी आदि शामिल हैं। यह रिपोर्ट नई आबकारी नीति (2021-22) में कमियों को भी सामने लाती है। इसमें नई आबकारी नीति के गठन के लिए बदलावों का सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनदेखी करना। राज्य के स्वामित्व वाली थोक इकाई के बजाय निजी संस्थाओं को थोक लाइसेंस प्रदान करना, प्रति बोतल वसूले जाने वाले आबकारी शुल्क के स्थान पर लाइसेंस शुल्क में उत्पाद शुल्क का अग्रिम प्रभार लगाना और आवेदक को अधिकतम 54 खुदरा दुकानें प्राप्त करने की अनुमति देना, जबकि एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें आवंटित की जाती हैं। लेखा परीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 2,026.91 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब समाप्त हो चुकी नीति के गठन में बदलाव के सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजर-अंदाज कर दिया था। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंसों के सरेंडर और शराब क्षेत्रों के लिए पुनः निविदा जारी करने में विभाग की विफलता के कारण आबकारी विभाग को 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए लाइसेंस धारकों को दी गई 144 करोड़ रुपये की अनियमित छूट पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसे वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद मनीष सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी थी।

अपमान याद कर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की आंखें छलकी

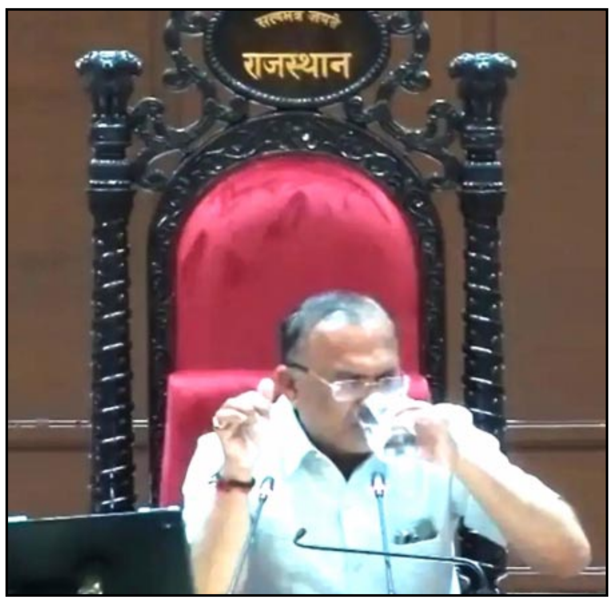

जयपुर (हिंस)। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को सदन में रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने व अपशब्द कहने के आरोप लगाए। देवनानी ने कहा कि मैं भी पांच बार से सदन में आ रहा हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। यह सब सुनने के बाद मुझे भी यह लगता है कि वह विधायक बनने के योग्य भी नहीं है लेकिन इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। विधानसभा में कांग्रेस के बायकॉट के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। देवनानी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रति कथित अपमानजनक शब्दों के बाद सदन के अंदर मचे हंगामे को लेकर सफाई दी। कांग्रेस विधायक ही गतिरोध के लिए पूरी तरह दोषी है। उन्होंने कहा कि मैंने गतिरोध दूर करने की पूरी कोशिश की लेकिन समझौते के अनुसार कांग्रेस विधायकों ने अपनी बात का पालन नहीं किया। सदन में अपनी इस बात को कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष का दो बार गला भर आया और आंसू भी छलक गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा कल बोली गई, उससे मैं बेहद आहत हूं। ऐसा सदस्य विधानसभा में रहने योग्य नहीं है। अब से कोई भी सदस्य यदि आसन की गरिमा भंग करेगा, तो वह स्वत: निलंबित माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सदस्य स्पीकर के डायस तक पहुंचेगा या अव्यवस्थित व्यवहार करेगा, तो उसे स्वत: ही निलंबित मान लिया जाएगा। अब इसके लिए कोई प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन मैं ऐसे शब्द सुनने के लिए अध्यक्ष नहीं बना हूं। स्पीकर के इस भावुक बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। देवनानी ने विधानसभा में कांग्रेस के निलंबित विधायक गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आसन को देखकर अपशब्द कहे जाने पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आसन का सम्मान होना चाहिए और उन्हें लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को कभी भी सदन में आने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हालांकि यह बात सदन तय करेगा कि ऐसे आचरण वाले विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। देवनानी के भावुक बयान के बाद सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने कहा कि अगर कोई सदस्य बार-बार सदन की गरिमा भंग करता है, तो उसकी सदस्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। देवनानी के भावुक होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके चेंबर में पहुंचे। उनके साथ विधानसभा में मौजूद कई मंत्री और बीजेपी विधायक भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर सदन की गरिमा बनाए रखने और गतिरोध खत्म करने को लेकर चर्चा की।

सीबीआई की जोधपुर टीम ने भीलवाड़ा में ईपीएफओ कर्मचारी को किया ट्रैप

जोधपुर (हिंस)। जोधपुर सीबीआई की टीम ने भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए ईपीएफओ के कर्मचारी अक्षय मीणा उर्फ कृष्ण कांत को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक विधवा की पेंशन शुरू करने के बदले रिश्वत मांगे जाने के मामले में की गई इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर दोपहर बाद उसे दुबारा कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सीबीआई के अनुसार भीलवाड़ा के हुरडा तहसील के तसवारिया में हरिपुरा निवासी जसराज कुम्हार की ओर से सीबीआई जोधपुर में शुक्रवार को एक शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसके पिता भंवरलाल आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड (मयूर मिल) में काम करते थे। वहां से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 819 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। गत 24 जुलाई 2021 को परिवादी के पिता का निधन हो गया। इसके बाद मृतक की पत्नी नोरतीदेवी की पेंशन शुरू होनी थी लेकिन अब तक यह पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। इसी मामले को लेकर परिवादी भीलवाड़ा स्थित ईपीएफओ कार्यालय पहुंचा और वहां कार्यरत बाबू अक्षय मीणा से मिला। तब उसने विधवा की पेंशन शुरू कराने की एवज में रिश्वत मांगी। सीबीआई की टीम ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन

कराया, तो उसमें भी रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इस पर टीम ने ट्रैप प्लान किया और जोधपुर से सीबीआई की टीम रविवार को भीलवाड़ा पहुंची। वहां आरोपी क्लर्क/डाटा एंट्री ऑपरेटर अक्षय मीणा उर्फ कृष्ण कांत ने परिवादी से पानसर चौराहा पर देर शाम जैसे ही पांच हजार रुपए की रिश्वत ली, तो सीबीआई की टीम ने उसे पकड़ लिया। बाद में सीबीआई टीम उसे गिरफ्तार कर जोधपुर ले आई। यहां सोमवार को उसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया। इस प्रकरण में आरोपी से पूछताछ के बाद मंगलवार दोपहर सीबीआई ने उसे दुबारा कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि (26 फरवरी) के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव परम तपस्वी एवं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा योग साधना के शीर्षदेव हैं। उनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। शर्मा ने कहा कि शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि हम अपने भीतर सत्य व ज्ञान को आत्मसात कर प्राणीमात्र के कल्याण का संकल्प लें।

पंजाब विधानसभा में राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति का मसौदा रद्द करने का प्रस्ताव पारित

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति के मसौदे को किसान विरोधी बताते हुए रद्द कर दिया गया है। इस मुद्दे पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मसौदे को पूरी तरह से राज्य के हितों के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने भाजपा पर पंजाब विरोधी का आरोप लगाया। मंगलवार को राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विधानसभा में राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति मसौदे को रद्द करने के प्रस्ताव को पेश किया। बाद में सदन में बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मसौदे का केंद्र सरकार को लिखित जवाब भेजकर कड़ा विरोध कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे को राज्य सरकार पूरी तरह से रद्द कर दिया है क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य के हितों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सिंह मान ने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री अपनी सरकार की ओर से किसानों के लिए की गई पहलों के बारे में बहुत दम भरते हैं, लेकिन दिल से वह और उनकी सरकार किसानों, खासकर पंजाब के

किसानों के साथ दुश्मनी भरा व्यवहार अपनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के कारण प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई, जबकि उन्होंने किसानों के साथ इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि पंजाब के किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद मजबूर होकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार कृषि विपणन राज्य का विषय है। उस समय के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि कृषि गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती हैं और हर राज्य की स्थिति अलग होती है क्योंकि राज्य अपने फसली चक्र, विपणन ढांचे की स्थिति और स्थानीय जरूरतों को समझने की बेहतर स्थिति में होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि संबंधी नीतियां राज्य की आवश्यकताओं, परिस्थितियों और चुनौतियों के आधार पर बनाई जा सकें। इस नीति के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति किसानों के लंबे विरोध के बाद भारत सरकार द्वारा 2021 में रद्द किए गए तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को पुन: लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कृषि मंडीकरण भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार को ऐसी कोई नीति लाने के बजाय इस विषय पर आवश्यकता अनुसार उचित नीतियां बनाने के लिए यह मामला राज्य की समझ पर छोड़ देना चाहिए। इससे पहले बहस के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जब कृषि कानून आए थे, तब उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं और उनके लिए मौत का वारंट साबित होंगे। बाजवा ने कहा कि किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। इसके बाद सरकार को कानून वापस लेने पड़े। उन्होंने भाजपा को पंजाब विरोधी (एंटी-पंजाब) बताया और कहा कि भाजपा राजनीतिक और आर्थिक रूप से पंजाब को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 8, 000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। बाजवा ने कहा कि अगर पंजाब सरकार सच में पंजाब के हक की लड़ाई लड़ना चाहती है तो तगड़े वकील खड़े करे और मोदी के घर के बाहर धरना दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा किया जाता है तो वह भी सरकार का समर्थन करेंगे। बाजवा ने कहा कि भले ही सदन में वह सरकार से लड़ते हैं, लेकिन पंजाब की भलाई के लिए सभी दलों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब के हक की रक्षा की जा सके।

पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 1274 इमिग्रेशन कंपनियों में की छापेमारी

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 1274 इमिग्रेशन फर्मों पर छापेमारी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के निर्देशानुसार सोमवार देर रात तक राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया। यह कार्रवाई अमेरिका से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने की पृष्ठभूमि में चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। स्पेशल डीजीपी कानून-व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि पुलिस टीमों ने डिफॉल्टर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कम से कम 24 एफआईआर दर्ज की हैं और उनमें से सात ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सीपी/एसएसपी को राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में विशेष पुलिस टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया था ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंट फर्मों की जांच की जा सके। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि सभी सीपीज/एसएसपीज को उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत, सभी ट्रैवल एजेंटों को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जो पांच वर्षों के लिए वैध होता है और अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को अपने लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना, ग्राहकों और सेवाओं का रिकॉर्ड रखना और विज्ञापन या सेमिनार आयोजित करने से पहले अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।

चुनावी समर में सीएम की विजय संकल्प यात्रा से बदलेगा माहौल

सोनीपत (हिंस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सोनीपत में भव्य रोड शो के माध्यम से चुनावी समरा में मेयर उपचुनाव के लिए भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचने माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वागत के लिए भाजपा संगठन व शहर की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने अपने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान दावा किया कि इस विजय संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में शहर वासी व पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। भाजपा की ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित

करेंगे। मंगलवार देर शाम शहर के अग्रसेन भवन में आयोजित सभा में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का अभूतपूर्व स्वागत किया और विजय संकल्प यात्रा में पूरे जोर शोर से हिस्सा लेने की घोषणा की। भाजपा के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने कहा बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजय संकल्प यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा। विजय संकल्प यात्रा शहर के अग्रसेन चौक से शुरू होकर मुरथल अड्डा, बस अड्डा, गीता भवन चौक, फ्लाईओवर, मिशन चौक से होते हुए कालूपुर चुंगी पर संपन्न होगा। राजीव जैन ने मंगलवार को आईटीआई चौक, कामी रोडश्री श्याम रस प्रचार मंडल, मैप्सको सिटी, छोटूराम चौक, आदर्श नगर, प्रगति नगर, लहराड़ा, सेक्टर-14 स्थित आरोग्या फिजियोथैरेपी सेंटर, भाटान मोहल्ला, राजीव कॉलोनी, बालाजी मंदिर के पास आदि जगहों पर सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विजय संकल्प यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत की जनता की सुविधाओं को लेकर करोड़ों रुपए के एन्हांसमेंट केसों को मंजूरी दी है। अब निगम क्षेत्र के सफाई कर्मियों को वेतन के लिए बार-बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से सफाई कर्मियों व पंप ऑपरेटरों में खुशी की लहर है। जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनहितैषी नीतियों पर पूरा भरोसा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत की शानदार हैट्रिक ने यह साबित किया है कि प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा के सशक्त और सक्षम नेतृत्व व सुशासन की नीतियों में हैं।

निकाय चुनाव में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी एफआईआर

रोहतक (हिंस)। निगम चुनाव में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी लाईसेंस धारकों को तुरंत हथियार जमा करवाने को भी कहा गया है। इस बारे में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़टा तथा नगर निगम रोहतक के आम चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक राज नारायण कौशिक की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सामान्य पर्यवेक्षक राज नारायण कौशिक ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं, डैसबोर्ड पर मतदान पार्टियों द्वारा अपडेट, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करने बारे आवश्यक हिदायतें दी। उपायुक्त धीरेंद्र खड़टा ने निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए आयोजित किए गए प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी दूसरे प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई कर्मचारी दूसरे प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चुनाव तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे चुनाव सामग्री का इंडेंट तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रोंग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा पोल डेसबोर्ड का संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के अलावा वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर भी मतदान बूथ के साथ मैपिंग किए जाए। धीरेंद्र खड़टा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम रोहतक तथा नगर पालिका कलानौर के आम चुनाव के लिए स्थापित किए गए मतदान केंद्रों में से संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए है।

वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता की जांच करवाने का आश्वासन

जयपुर (हिंस)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में आश्वस्त किया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है। प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अल्पलंख्यक समुदायों को लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना के साथ-साथ राज्य सरकार द्वार संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, निश्शुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय आदि योजनाओं के माध्यम से समस्त अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे पहले विधायक युनूस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण तथा इन योजनाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में गत तीन वर्षों में लाभान्वित किए गए लोगों की योजनावार संख्यात्मक सूची प्रस्तुत की।

पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब सरकार ने विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को दिल्ली में हाल ही में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब सरकार का आरोप है कि दिल्ली में बनी भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करते ही अपने कार्यालयों में लगे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को उतार दिया। पंजाब के संसदीय कार्यमंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते

हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों में लगे बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को उतारना भाजपा की दलितों व शहीदों के प्रति सोच को दर्शाता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा की आलोचना करते हुए इस प्रस्ताव को सेकेंड किया। इसके बाद विधायक डॉ. सुखविंद्र सिंह, नक्षत्र पाल सिंह ने इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपना समर्थन दिया। सदन में जिस समय यह प्रस्ताव पेश किया गया, उस समय अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेता व सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी विधानसभा में पारित करने की मांग की। इस पर संसदीय कार्यमंत्री अमन अरोड़ा ने राहुल गांधी के मनमोहन कैबिनेट के फैसलों संबंधी कागजों को फाड़ने की घटना पर माफी मंगवाएं तो पंजाब सरकार इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके भेज देगी। अमन अरोड़ा के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पंजाब विधानसभा में दिल्ली की भाजपा सरकार के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर तथा शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को दफ्तर से हटाना गलत है। इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित करके भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी कि शहीदों को उचित मान सम्मान दिलवाना यकीनी बनाया जाए।

राजस्थान के 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा कल से

जयपुर (हिंस)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 27 से 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2024 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में नकल रोकने व पारदर्शिता बनाए रखने के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जा रहा है। बोर्ड पहली बार परीक्षा में फेस रिकॉग्नाइजेंशन तकनीक का उपयोग करेगा। इसमें प्रवेश-पत्र में लगी फोटो का बार कोड के जरिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी से मिलान किया जाएगा। उसके फिंगर प्रिंट भी लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखेगा। परीक्षा के दौरान केंद्र लाइव देखे जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार परीक्षा से एक घंटा पहले बंद हो जाएगा। अभ्यर्थी सादा कपड़ों, चप्पल या सैंडल में ही परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की चेन या मैटल का आभूषण पहन कर आने की मनाही है। बोर्ड प्रशासक महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 27 व 28 फरवरी को राजस्थान के समस्त जिलों में किया जाएगा। 27 फरवरी को प्रथम पारी में लेवल-1 तथा द्वितीय पारी में लेवल-2 के लिए तथा 28 फरवरी को तृतीय पारी में लेवल-2 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। रीट परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत परीक्षार्थी 14 लाख 29 हजार 822 है। इसमें लेवल-1 में कुल परीक्षार्थी तीन लाख 46 हजार 625, लेवल-2 में कुल परीक्षार्थी नौ लाख 68 हजार 501 तथा दोनों लेवल के लिए कुल परीक्षार्थी एक लाख 14 हजार 696 पंजीकृत है। इसमें 27 फरवरी को प्रथम पारी में चार लाख 61 हजार 321, द्वितीय पारी में पांच लाख 41 हजार 599 तथा 28 फरवरी को पांच लाख 41 हजार 598 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। रीट परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए हैं। सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि अजमेर में 57, अलवर में 74, बालोतरा में 11, बांसवाड़ा में 34, बारां में 34, बाड़मेर में 48, ब्यावर में 17, भरतपुर में 93, भीलवाड़ा में 51, बीकानेर में 45, बूंदी में 23, चित्तौड़गढ़ में 22, चुरू में 47, दौसा में 47, डीग में 41, धोलपुर में 31, डीडवाना-कुचामन में 20, डूंगरपुर में 44, हनुमानगढ़ में 39, जयपुर में 233, जैसलमेर में 13, जालोर में 26, झालावाड़ में 44, झुंझुनूं में 64, जोधपुर में 75, करौली में 26, खैरथल-तिजारा में 12, कोटा में 67, कोटपुतली-बहरोड़ में 36, नागौर में 25, पाली में 21, फलौदी में 12, प्रतापगढ़ में 26, राजसमंद में 21, सलूम्बर में 16, सवाई माधोपुर में 34, सीकर में 51, सिरोही में 24, श्रीगंगानगर में 35, टोंक में 37 तथा उदयपुर में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश-पत्र, नीला अथवा काला पारदर्शी बॉल प्वाइंट पेन, कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल आधार कार्ड पहचान-पत्र एवं इसके अनुपलब्ध होने पर ड्राइविंग लाईसेंस, निर्वाचन पहचान-पत्र आदि अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान-पत्र मय स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के दो घण्टे पूर्व पहुंचना होगा। परीक्षार्थी को प्रथम पारी में प्रात: नौ बजे तथा द्वितीय पारी में अपराह्न दो बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के प्रति संवेदनशील : देवस्थान मंत्री

जयपुर (हिंस)। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में 161 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाने की घोषणा की है। इनमें से प्रदेश के 552 मंदिरों पर 101 करोड़ रुपए तथा प्रदेश से बाहर के 41 मंदिरों में 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में देवस्थान विभाग

में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। साथ ही, भोगराग को दोगुना करते हुए तीन हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है।

संपादकीय

आज़ादी का दुरुपयोग

पिछले दिनों एक विवादास्पद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संबंधित कानूनों के अनुपालन की जरूरत महसूस करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिये एडवाइजरी जारी की है। निस्संदेह यह वक्त की जरूरत है। दरअसल, हाल ही में एक यूट्यूबर की अभद्र टिप्पणी से पैदा हुए विवाद पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी। केंद्र सरकार की पहल को शीर्ष अदालत के सख्त रुख के आलोक में देखा जा रहा है। पारिवारिक मूल्यों वाले भारतीय समाज में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हुए अमर्यादित व संवेदनहीन टिप्पणी के मामले गाहे-बगाहे प्रकाश में आते रहते हैं। यही वजह है कि इलाहाबादिया प्रकरण में कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज कर किए गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से राहत तो दी मगर सख्त टिप्पणी भी की थी कि वे दिमागी गंदगी को थोप रहे हैं, जिससे समाज शर्मसार हुआ है। लेकिन इस प्रकरण ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के नियमन की बहस को नये सिरे से शुरू कर दिया। हालांकि, आपातकाल के सीमित कालखंड को छोड़ दें तो देश में हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट समेत कई उच्च न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन आजादी के अतिक्रमण के बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेतु एडवाइजरी जारी करते हुए संबंधित कानून के सभी प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निस्संदेह, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के निर्धारण की आवश्यकता है। हाल के दिनों में डिजिटल मंचों पर अश्लीलता व हिंसक अभिव्यक्ति के चलते इनके नियमन की जरूरत महसूस की जा रही है। खासकर पारिवारिक जीवन मूल्यों का अतिक्रमण करने वाली टिप्पणियों पर रोक जरूरी है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता तो बहुत संभव है कि सरकारी निगरानी बढ़ जाए। दरअसल, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस बाबत बनी संसदीय समिति से कहा है कि समाज में इस बात को लेकर रोष है कि अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण करके हिंसक व अश्लील सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है। वहीं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का कहना है कि इसके नियमन के लिये कुछ कानून तो हैं लेकिन वर्जित सामग्री के नियमन के लिये नया प्रभावी कानून होना चाहिए। ऐसी राय देश के जनप्रतिनिधियों, अदालतों तथा कुछ वैधानिक संस्थाओं ने व्यक्त की है। देश की शीर्ष अदालत का मानना रहा है कि यूट्यूब जैसे मंचों पर सामग्री साझा करने पर नियंत्रण हेतु कानून निष्प्रभावी नजर आते हैं। अब नये मीडिया मंचों पर विवादास्पद सामग्री पर अंकुश लगाने के लिये कानून में संशोधन की भी बात कही जा रही है। इसकी वजह यह भी है कि परंपरागत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस बाबत बने कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन नए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिये प्रभावी कानून नहीं है। निश्चित रूप से संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार की पहल को शीर्ष अदालत के सख्त रुख के आलोक में देखा जा रहा है। पारिवारिक मूल्यों वाले भारतीय समाज में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हुए अमर्यादित व संवेदनहीन टिप्पणी के मामले गाहे-बगाहे प्रकाश में आते रहते हैं। यही वजह है कि इलाहाबादिया प्रकरण में कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज कर किए गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से राहत तो दी मगर सख्त टिप्पणी भी की थी कि वे दिमागी गंदगी को थोप रहे हैं, जिससे समाज शर्मसार हुआ है। लेकिन इस प्रकरण ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के नियमन की बहस को नये सिरे से शुरू कर दिया। हालांकि, आपातकाल के सीमित कालखंड को छोड़ दें तो देश में हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट समेत कई उच्च न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन आजादी के अतिक्रमण के बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेतु एडवाइजरी जारी करते हुए संबंधित कानून के सभी प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निस्संदेह, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के निर्धारण की आवश्यकता है। हाल के दिनों में डिजिटल मंचों पर अश्लीलता व हिंसक अभिव्यक्ति के चलते इनके नियमन की जरूरत महसूस की जा रही है।

किसानों पर बकाया कर्जों को अगर माफ कर दिया जाए तो किसान जहां ज्यादा खुशहाल होंगे

औपचारिक और बेहतर कर्ज से किसानों की बढ़ती उत्पादकता

उमेश चतुर्वेदी

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 46.1 प्रतिशत हिस्सा खेती-किसानी और उससे जुड़े कार्यों से अपनी रोजी-रोटी चलाता है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार देश के 12 करोड़ किसान परिवार सीमांत हैं। इनमें करीब 35 प्रतिशत की जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, जबकि 69 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। आंकड़ों के अनुसार देश के 82 प्रतिशत किसान छोटे या सीमांत हैं। जिनकी जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, उनकी खेती से सालाना आमदनी आठ हजार रूपए के आसपास है। जाहिर है कि देश के किसानों के बड़े हिस्से के पास बिक्री के लिए उपज ही नहीं होती। खेती के जरिए वे जो अन्न या सब्जी उपजाते हैं, उनका इस्तेमाल अपने खाने-पीने में ही करते हैं।

साल 2025-26 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को मिलने वाले तीन लाख रूपए के कर्ज को बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसका जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक्स पर लिखा है कि इससे सब्जी-फल, हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वे खेती में ज्यादा पैसे लगा सकते हैं, ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय हैं। हालांकि किसान संगठनों को लगता है कि इसका जितना फायदा सोचा जा रहा है, उतना नहीं होने वाला है। किसान संगठनों की मांग है कि किसान क्रेडिट की सीमा बढ़ाने के साथ ही किसानों पर बकाया कर्जों को अगर माफ कर दिया जाए तो किसान जहां ज्यादा खुशहाल होंगे। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 46.1 प्रतिशत हिस्सा खेती-किसानी और उससे जुड़े कार्यों से अपनी रोजी-रोटी चलाता है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार देश के 12 करोड़ किसान परिवार सीमांत हैं। इनमें करीब 35 प्रतिशत की जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, जबकि 69 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। आंकड़ों के अनुसार देश के 82 प्रतिशत किसान छोटे या सीमांत हैं। जिनकी जोत 0.4 हेक्टेयर से कम है, उनकी खेती से सालाना आमदनी आठ हजार रूपए के आसपास है। जाहिर है कि देश के किसानों के बड़े हिस्से के पास बिक्री के लिए उपज ही नहीं होती। खेती के जरिए वे जो अन्न या सब्जी उपजाते हैं, उनका इस्तेमाल अपने खाने-पीने में ही करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था। उसके लिए जो कदम उठाए गए, उसी कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत भी थी। इसके फायदे हुए भी हैं। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया था, उसे पाना अब भी कठिन चुनौती बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान का कहना ठीक है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का फायदा किसानों को होगा। इसकी तस्दीक हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हुए कृषि सर्वेक्षण से जुड़े घरेलू स्तर के आंकड़ों का आकलन भी बताता है। घरेलू स्तर के आंकड़ों के जरिए कृषि में उत्पादकता और उसके जोखिम के साथ ही कृषि ऋण के प्रभाव का आकलन भी

किया गया था। इस आकलन के नतीजे बताते हैं कि अगर किसानों को समय पर उचित कर्ज मिलता है तो उससे उसकी उत्पादकता में 24 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दिखने लगती है। इससे किसानों को होने वाले नुकसान का जोखिम 16 फीसद तक कम हो जाता है। महाजनी सभ्यता और अनौपचारिक कर्ज व्यवस्था के जोखिम और उससे उपजे खराब हालात से जूझते किसानों की दयनीय और मार्मिक कहानियों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गोदान ऐसी ही कथाभूमि पर रचा गया गया है। उसे कृषक के दारूण जीवन की महागाथा कहा जाता ही है। बहरहाल यह अध्ययन मानता है कि किसानों को अगर औपचारिक क्षेत्र का ऋण मिलता है तो उसकी उपज और उसकी जिंदगी पर उस कर्ज का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जबकि अनौपचारिक यानी महाजनी कर्ज व्यवस्था का किसानों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। साफ है कि किसानों को अगर सही तरीके से औपचारिक कर्ज सही वक्त पर दीर्घकालिक अवधि के लिए मिले तो उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। कुछ अन्य अध्ययन भी बताते हैं कि अगर किसानों को समय पर दीर्घकालिक और औपचारिक कर्ज मिलता है तो उसकी खेती को जरूरतों को पूरा करने में उसे मदद मिलती है। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। किसान की उपज बढ़ जाती है, फसल तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसे बेचने के लिए सही बाजार तक पहुंच के लिए रकम नहीं होती तो उसे अपनी फसल और उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है। लेकिन अगर किसान को सही तरीके से औपचारिक कर्ज मिलता है तो उस पर तात्कालिक आर्थिक दबाव नहीं रहता और फ़सल के बाद के खर्चों को पूरा करने में उसे मदद मिलती है। अगर किसानों के पास कुछ पैसे रहते हैं तो उस पर घरेलू जरूरतों का दबाव नहीं झेलना पड़ता और उसे अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने में जहां सहायता मिलती है, वहीं इसके लिए उसे अपनी उपज सेंतमेत में बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ता। इस कर्ज से किसान अपने कृषि उपकरणों और दूसरी अवसंरचनाओं को आसानी से रखरखाव कर सकता है। अध्ययन बताते हैं कि समय बद्ध और सहूलियत भरे अधिक कर्ज के जरिए किसानों को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे कृषि आधारित और सहयोगी कामों को आगे बढ़ाने में मदद होती है। इस पूरी प्रक्रिया का असर यह होता है कि किसान की आर्थिक सुरक्षा मज़बूत हो जाती है। तब वह बाजार और अपने उपज की वाजिब कीमत का इंतजार भी कर सकता है। आर्थिक सहूलियत रहने से समय पर वह जरूरी खाद और दवाओं को खरीदकर उनका खेती में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही वह दूसरे खर्चों का दबाव भी नहीं महसूस कर सकता है। बीती 31 जनवरी को को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इनके जरिए किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। यह रिपोर्ट भी कहती है कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के चलते खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के 5.9 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट योजना का फायदा उठा रहे हैं। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने को ही ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि अपने कर्ज का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा कृषि और छोटे किसानों को दें। इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से औपचारिक कर्ज तो मिल ही सके, उन्हें महंगी दर पर अवशोषक अंदाज में मिलने वाली निजी कर्ज राशि पर निर्भरता ना रहे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अब साहूकार जैसे गैर-बैंकिंग कर्जदाताओं पर किसानों की निर्भरता घटकर 1950 के 90 फीसद की तुलना में 2022 में सिर्फ 25 फीसद रह गई। साफ है कि अब ज्यादातर किसान बैंक और संस्थागत स्रोतों से कर्ज ले रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक ताकत और उत्पादकता बढ़ रही है।

दृष्टि कोण

बैलों पर राजस्थान की पहल का स्वागत हो

राजस्थान सरकार की ओर से एक अच्छा फैसला आया है। सरकार बैलों से खेती करने वालों को 30 हजार रुपए वार्षिक सहायता देगी। यह निर्णय कृषि अर्थव्यवस्था की भारतीय समझ रखने वालों को समझ में आएगा। मशीनों से खेती करने वालों को तो अनेक प्रोत्साहन सबसिडी के रूप में दिए जाते हैं। मशीनों से लेकर मशीनों के ईंधन तक लगातार उनको सहायता दी जाती है। हिमाचल में पॉवर टिलर को 50 फीसदी तक सबसिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी पूरे काल तक जब तक वह मशीन काम करेगी उसे विदेश मुद्रा के द्वारा लाए गए ईंधन को उपलब्ध करवाना होगा। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही जो जोतें एक हेक्टेयर से छोटी हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर होने का मार्ग बैलों से खेती के माध्यम से ही निकल सकता है। किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां की 80 फीसदी जोतें एक हेक्टेयर से छोटी हैं, कुछ तो एक एकड़ से भी छोटी हैं। इनको लाभदायक बनाना खासी चुनौती का काम है। पॉवर टिलर से जुताई का एक बीघा के लिए 2 हजार रुपए तक लिया जा रहा है। ऊपर से धुआं और शोर अलग से भेंट स्वरूप मिल रहा है। हर किसान अपना पॉवर टिलर ले भी नहीं सकता। और ले भी ले तो दो दिन के बाद सारा सीजन खाली पड़ा रहेगा। दूसरे, पहाड़ी खेती को आम तौर पर ही ज्यादा गोबर खाद की जरूरत रहती है क्योंकि भारी बरसात और ढलानदार जमीनों से हर साल खाद बह कर नीचे चली जाती है, जबकि हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए गोबर की खाद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जिसके अभाव में यह पहल भी सफल होना कठिन हो जाएगी। खेती देश में घाटे का सौदा होती जा रही है। इसी के चलते लोग खेती को छोड़ कर अन्य व्यवसायों की ओर मुड़ते जा रहे हैं। खेती लाभदायक तब तक नहीं हो सकती जब तक खेती को आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम नहीं किया जाता। खेती के लिए हमें अपने संसाधनों से ही काम चलाना सीखना होगा, जिससे कृषि व्यवसाय का पैसा कृषि व्यवसाय में ही घूमता रहे। मिसाल के लिए बैल से खेती करेंगे तो बैल किसान ही पैदा करेगा। किसान जब बैल खरीदेगा तो पैसा दूसरे किसान के पास ही जाएगा। एक किसान का व्यय दूसरे किसान की आमदनी बनेगा। और पैसा आपस में ही घूमता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भरता बनती जाएगी। आज मैं बैल खरीद रहा हूं, कल मैं बेच रहा हूंगा। जैविक खेती के लिए घर का खाद बिना बैंक के कर्ज के उपलब्ध होगा। जबकि मशीनी खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेशित वस्तुएं बाहरी क्षेत्रों उद्योग आदि से आएंगी, जिससे उद्योग तो बढ़ेगा, किन्तु खेती की कमाई उसी में चुक जाएगी। घाटे की खेती का दुश्चक्र इसी तरह आत्मनिर्भरता की ओर प्रस्थान से तोड़ा जा सकता है। यह ठीक है कि बड़ी जोत वाले किसानों के लिए यह कठिन है, किन्तु छोटी जोत वाले किसान दृढ़संकल्प करके एक बार इसे अपना लें तो धीरे-धीरे किसानी आत्मनिर्भर होगी और कर्ज से मुक्ति होने का रास्ता भी बनेगा जिसके कारण ही ज्यादातर आत्महत्याएं कृषि क्षेत्र में हो रही हैं। अपना बीज, अपना बैल, अपनी खाद, यही किसान का नारा होना चाहिए। जब तक यह तरीका कृषक अपना रहे थे तब तक कहीं भी किसान को आत्महत्या की जरूरत ही नहीं थी। यही अब अपनाना होगा, किन्तु थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जिससे फसलों की उपज भी कम न हो। हिमाचल का उदाहरण लें तो यहां 9.97 लाख कुल जोतों में से 7.12 लाख जोतें एक हेक्टेयर से कम हैं। उन सभी को बैलों पर सबसिडी देकर बैल से खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जिससे पेट्रोल, डीजल पर खर्च विदेशी मुद्रा भी घटेगी और किसान बैंक कर्जों से भी बचेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 13.57 फीसदी है, जबकि खेती से 58.37 फीसदी रोजगार पैदा हो रहे हैं। इसलिए खेती के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। न्याय का भी यही तकाजा है कि बैल से खेती करने वाले को मशीन से खेती करने वाले के बराबर ही अधिमान दिया जाए। हालांकि बैल से खेती को यदि थोड़ा अधिक भी सहयोग दिया जाए तब भी उससे देश पर ज्यादा बोझा नहीं पड़ेगा क्योंकि बैल से खेती करने के कारण पैसा देश में ही रहेगा और किसान के हाथ में ही किसान द्वारा खर्च किया गया रुपया पहुंचेगा। यह काम खेती और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के ही हित में है, इसलिए सरकारों को राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए किसान हित में स्वावलंबी कृषि व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आगे बढने के लिए पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ कार्य शुरू करना चाहिए। इस दिशा में सफलता के लिए बैल चालित मशीनों का अपना महत्व है।

कुछ अलग

एक महाकुंभी से मुलाकात

करीब एक महीने के बाद झुन्नू लाल जी के दर्शन नसीब होते ही मैं धन्य हो उठा। पिछली बार जब मिले थे तो कांधे पर एक पि_, एक हाथ में थैला और दूसरे में डंडा लिए प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। लेकिन उन भावों के पीछे उनके चेहरे पर छपे भय, दीनता और दायस्ता के भाव उसी तरह मुखर थे, जैसे एक आम धार्मिक व्यक्ति और लोकतंत्र के मारे आदमी के मुखमंडल पर होते हैं। कुंभ स्नान के बाद उनका परलोक सुधरने, स्वर्ग में सीट पक्की होने और दुनिया भर में देश का डंका बजने के बावजूद उनके चेहरे पर अंकित भय, दीनता और दास्यता के भावों में कोई अंतर न पाकर मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ, पर दुःख अवश्य हुआ। मैंने उनसे पूछा, 'कुंभ में स्नान के बाद आपको मुक्ति मिल चुकी है, स्वर्ग में अब आपकी सीट पक्की है, आपका परलोक सुधर चुका है। आपकी पार्थिव यात्रा मुकम्मल होने पर आपको लिवाने के लिए यमराज भैंसे पर नहीं पुष्पक विमान में आएंगे। पूरी संभावना है कि अगली बार आपको इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अडानी, अम्बानी या किसी शेख़ के घर में जन्म मिले। पर आप सनातन धर्म की ध्वजा के अग्रवाहक हैं। आप अडानी या अम्बानी के घर ही पैदा होना चाहेंगे। इलॉन मस्क और बिल गेट्स तो ईसाई हैं और शेख़ मुस्लिम। लेकिन कुंभ में नहाने के बावजूद आपके चेहरे पर पसरे भय, दीनता और दास्यता के भावों में कोई अंतर क्यों नहीं आया।' झुन्नू लाल जी मुझे घूरते हुए बोले, 'नए भारत में हो रहे महाकुंभ-2025 की अमर गाथा को कुछ हज़ार या लाख यहां तक कि करोड़ों-अरबों शब्दों में भी बयां करना और लिखना नामुमकिन है। इसके बावजूद तुम्हारे जैसे काफिर हिंदू धर्म पर तंज़ कसने से बाज़ नहीं आते। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पापी जीवन पर। तुम्हारे जैसे धर्म और देशद्रोही उलटा-सीधा कहने और लिखने की कोताही कर रहे हैं। पर तुलसी दास जी ने ठीक ही कहा है- जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तुम्हारे जैसे पापियों को घोर नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम भी विपक्षियों की तरह ईर्ष्या में सुलग रहे हो। मेला चले एक महीने से अधिक हो चुका है। निकम्मे और ज़िम्मेदार अधिकारी असफल दिख रहे हैं। पर भोले भंडारी की कृपा देखो। यह कहने में संकोच नहीं कि तीर्थराज प्रयाग ही इसे चला रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान के पर्व पर भगदड़ से लेकर रास्ता जाम और कुंभ मेले के वीआइपी सेंट्रिक होने का वितंडा घडने के लिए तुम्हारे जैसे गद्दार और धर्म के दुश्मन ही ज़िम्मेवार हैं। धर्म की राह में अगर कुछ सैंकड़ों आदमी सीधे गोलोक सिधार गए तो क्या हुआ? भोले शिव स्वयं उनको परमधाम ले जाने के लिए प्रयागराज में परिवार सहित उतरे हैं।' मेले की अव्यवस्था और भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने की ख़बरों को गोदी मीडिया द्वारा दबाए जाने से आहत होने के बावजूद मैंने अपने आपको संभालते हुए कहा, 'निःसंदेह इस आयोजन के प्रति आम आदमी की निष्ठा असंदिग्ध है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो 144 सालों बाद आने वाले इस महाकुंभ को कौन आयोजित करता। विदेशी ताकतें इस महा आयोजन को असफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रही हैं। विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहा है।' मेरे मुंह से प्रशंसा भरे शब्द सुनने के बावजूद वह मेरी तरफ संशय भरी नज़रों से देखते हुए बोले, 'मुझे प्रसन्नता है कि तुम पहली बार किसी अंधभक्त की तरह बात कर रहे हो। यह भी भोले की ही कृपा है कि तुम्हारे जैसे पापियों को भी सद्बुद्धि आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल, गरिमामयी पारदर्शी, ओजस्वी और प्रेरणामयी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक सभी विधर्मी और तुम्हारे जैसे धर्मद्रोही धर्म की राह पर अग्रसर होंगे।

देश दुनीया से

उनकी भी सोचें जिनसे किसी ने हमदर्दी नहीं जतायी

पंजाब पांच दरियाओं की धरती,यूनानी जिसे पेंटापोटामिया (इसका अर्थ भी वही है) पुकारते थे। वह धरा जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेद और महाभारत की रही। इसी भूमि पर सिकंदर ने झेलम के तट पर पोरस से युद्ध किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, एंग्लो-सिख युद्ध यहीं लड़े गए – पंजाब जैसी भूमि के उदाहरण कम ही हैं, जिसने सदियों तक आक्रमण, तबाही और लूटपाट झेली हो। हम शुरुआत करते हैं 1947 के बाद से, यानी वह घड़ी जो एक शानदार युग की सुबह होने वाली थी। यह प्रभात शेष भारत में खुशी और धूप की तरह खिली, सिवाय पंजाब और बंगाल सूबों के। जो विभाजन हुआ, वह काफी हद तक पंजाब और बंगाल का था। अंग्रेजों द्वारा खींची गई और कांग्रेस नेतृत्व, गांधी और जिन्ना द्वारा स्वीकार की गई एक काल्पनिक रेखा ने पंजाब को बांट दिया। यह पंजाब के शरीर और आत्मा के टुकड़े करना था। इसने अपने पीछे हत्या, बलात्कार और तबाही की सुनामी छोड़ी। ऐसा रक्तपात पहले कभी नहीं हुआ और संभवतः इतिहास का विशालतम जबरन पलायन। यह बड़ी उथल-पुथल कदाचित 1950 के दशक के शुरू में पश्चिमी दुनिया की ओर शुरू पलायन की पहली लहर के अंतर्निहित मुख्य कारणों में से एक थी। शुरू में, यह मामूली थी, अधिकांशतः यूके और उसके बाद कनाडा की तरफ। दो विश्व युद्धों में इस इलाके का योगदान बहुत बड़ा था, और लौटकर आए फौजी यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व से कहानियां व अनुभव सुनाते थे। मनुष्य सदा बेहतर जिंदगी तलाशता रहा, और जब घर पर मौके निराशाजनक हों, तो वह बाहर की ओर देखता है। यहां देश में, पंजाबी जीवट धीरे-धीरे तारी हुई और अच्छे नेतृत्व और प्रशासन की मदद से, हमने बिखरे टुकड़े सहेजे और विभाजन की भयावहता पर काबू पाया और लगभग सामान्य जीवन जीने लगे। कुछ दशकों तक लगा कि हम समृद्धि-शांति की राह पर हैं। परंतु यह मृगतृष्णा साबित हुई और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां उभरने लगीं। पहले से बंटे पंजाब में और विभाजन की मांग की गई जो अंततः सफल हुई। अकाली सिख वर्चस्व वाला राज्य चाहते थे, वहीं पहाड़ी लोगों ने अपने लिए सुरक्षित सूबा मांगा, ठीक यही हरियाणा के लोगों ने किया। संयुक्त पंजाब को तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। चंडीगढ़, जिसे लाहौर के स्थान पर बतौर आधुनिक राजधानी विकसित किया गया था, वह भी जाती रही। विभाजन से पूर्व के पंजाब सूबे के पांच प्रशासनिक संभाग थे – जलंधर (अब जालंधर), लाहौर, दिल्ली, मुल्तान और रावलपिंडी। इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा गया, लेकिन असल में इसने पंजाब के पतन की शुरुआत की क्योंकि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और पतनशील नेतृत्व ने अफरातफरी पैदा की। पहाड़ और उनके जंगल व जलीय स्रोत हिमाचल में वहीं राष्ट्रीय राजधानी की निकटता, इसके फायदे और यमुना किनारे की भूमि हरियाणा में चले गए। इस क्षेत्र का नाम बदलकर अब 'लघु आब' कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अब 'पंज-आब' कहलवाने लायक नहीं रहा। अधिकांश विकास सूंचकाकों में ये तीनों राज्य फिसड्डियों में आते हैं। लोकतंत्र में वोट संख्या का महत्व होता है, जाहिर है संसद में 80 सीटों वाले राज्य की आवाज़ और उपस्थिति 10 या 13 सीटों वाले राज्य की तुलना में कहीं ज़्यादा है। धीरे-धीरे युवाओं का कट्टरपंथीकरण होता गया और धर्म के नाम पर हिंसक आंदोलन के नये नारे देने वाला उग्रवादी नेतृत्व उभरा। इसके पीछे कई किस्म के नेताओं के हाथ-दिमाग थे, हालात बनते गए और हिंसा बढ़ती गई, उधर शासन की शक्ति बढ़ती गई। यह सब ऑपरेशन ब्लू स्टार त्रासदी और इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना, जिसके बाद भारत भर में सिखों का कत्लेआम हुआ व समय रहते उस पर अंकुश नहीं लगाया। अगला दशक व्यर्थ गया, जिसमें रोजाना बेगुनाहों की हत्याएं होती रहीं। हमारे उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी ने स्थिति का जमकर फायदा उठाया, चरमपंथ और आतंकवादी आंदोलन की आड़ में छद्म युद्ध चला दिया। पंजाब को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान 1948, 1965 और 1971 में बड़ी लड़ाइयां हार चुका था, वह बदला लेने की ताक में था और यह मौका हमने तश्तरी में रखकर दे दिया (1965 में भी पंजाब ने ही युद्ध का खमियाजा भुगता, क्योंकि ज्यादातर लड़ाई यहीं तक सीमित रही)। पंजाब में हालात फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे और चुनाव होने तक, लगभग एक दशक राष्ट्रपति शासन रहा। जनता की मांग के बावजूद, पंजाब के लिए कोई वित्तीय पैकेज या विशेष विकास कार्यक्रम नहीं दिया गया, ताकि बेगुनाह लोगों के दशकों झेले आघातों की भरपाई हो पाती। सनद रहे कि दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी तटों वाले प्रायद्वीप के विपरीत, पंजाब गैर-समुद्र तटीय राज्य है, व्यापार की एकमात्र राह उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया की तरफ खुलती है। किंतु यह रास्ता भी बंद हो गया और खोलने की अपीलें अनसुनी रहीं। इस घटनाक्रम ने 1980 के दशक में पलायन की दूसरी और ज्यादा बड़ी लहर को जन्म दिया। राहत और रोजगार पाने की आस में पश्चिमी देशों का रुख किया। फिलहाल, तीसरी लहर जारी है क्योंकि युवा शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर मुल्कों में भविष्य देख रहे हैं। मैं इसे तीसरी लहर कहता हूं क्योंकि इसमें अब वे युवा शामिल हैं जिन्हें विरासत में कर्ज में डूबा राज्य मिला (पंजाब पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का ऋण है) और उसके पास अवसर या उन्हें बनाने वाली शिक्षा नदारद है। इंटरनेट जागरूकता लाया, और आगे आकांक्षा को जगाया है। युवा पश्चिमी दुनिया का जीवन और सुख पाना चाहते हैं। उन्हें यहां यह सब नहीं मिलता और न ही इसे बनाने के साधन और माहौल हैं। पंजाब से लोग वैध-अवैध पलायन कर रहे हैं। राजनेता, पुलिस और ट्रैवल एजेंटों का गठजोड़ खुलेआम चल रहा है, ढेरों पैसे दिए जा रहे हैं। इसके लिए जमीन बेची जाती हैं, कर्ज लिए जाते हैं और रिश्तेदारों से रकम जुटाते हैं। अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग सेंटर खुले, वहां भी पैसे ऐंठे गए। यह सब खुलेआम चलता रहा व गांवों, कस्बों और सत्ता के गलियारों में, इसे आम बात मान लिया गया। किंतु, पंजाब की इस लूट को रोकने को कोई कदम नहीं उठाया गया।

आप का नजरीया

एक त्रासद तबाही का युद्ध

रूस यूक्रेन युद्ध के तीन साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी जारी है। रूस ने ऐसे प्रतिरोध की कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि अब समझौते, शांति और संवाद की एकतरफा कोशिशें भी की जा रही हैं। अमरीका-रूस के विदेश मंत्री स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में बातचीत की है। यूक्रेन और यूरोप को इस संवाद से बाहर ही रखा गया है। क्या यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्र अस्तित्व को नकारा गया है? क्या यूक्रेन की सहमति के बिना कोई युद्ध-समझौता हो सकता है? यूक्रेन का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमरीका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्तासीन होने के बाद उसने यूक्रेन की मदद करने से साफ इंकार कर दिया है। यूरोप अब यूक्रेन की सैन्य, आर्थिक मदद को लेकर विभाजित हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरोकार इतना है कि शांति स्थापित हो और यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए, तो वह राष्ट्रपति पद छोडने को तैयार हैं। रूस का साम्राज्यवादी रुख रहा है। इसी आधार पर उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर युद्ध छेड़ा था। रूस की सोच है कि यूक्रेन को संप्रभु देश होने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर इस युद्ध का निष्कर्ष क्या होगा? हमारा मानना है कि इस युद्ध में न तो कोई विजेता है और न ही कोई पराजित है। बल्कि रूस-यूक्रेन दोनों ही हारे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में विध्वंस, तबाही व्यापक स्तर पर हुई है। दोनों ही देशों को यह अनुभव हो गया होगा कि युद्ध की परिणति क्या होती है? युद्ध भी एक नए किस्म की निरंतर राजनीति का प्रतिरूप है। इस संदर्भ में ट्रंप, पुतिन, मोदी और यूरोपीय देश अपनी राजनीति के मोहरे चल रहे हैं। बहरहाल यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक त्रासद् तबाही वाला युद्ध साबित हुआ है। तबाही रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों में हुई है। दोनों के करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं। उनमें अधिकतर सैनिक थे। करीब 68.5 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोपीय देशों में हैं। करीब 1 करोड़ यूक्रेनी बेघर हुए हैं। उसके 8 लाख सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज कैसे होगा? बेघर होने वालों में करीब 20 लाख बच्चे भी हैं। यूक्रेन का 20 फीसदी जमीनी हिस्सा खो चुका है। 2024 में यूक्रेन का 4168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस ने कब्जा लिया। यूक्रेन के 10 बड़े शहर 'खंडहर' हो चुके हैं। रूस को भी कुल 109 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उसके 20 से अधिक पोत यूक्रेनी हमलों के कारण 'काला सागर' में डूब चुके हैं। रूस के बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि भी तबाह हुए हैं। युद्ध के कारण ही रूस के औसत जीवन-स्तर में 35 फीसदी की गिरावट आई है। तो किस आधार पर रूस खुद को युद्ध का विजेता घोषित कर सकता है? बेशक युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किए हैं, लेकिन ट्रंप 'शांति का नोबेल पुरस्कार' हासिल करने के मद्देनजर ऐसे भेदभावपूर्ण प्रयास न करें। संवाद की मेज पर दोनों देशों के प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए। इस युद्ध ने विश्व की 'सप्लाई चेन' को बुरी तरह प्रभावित किया है। रूस-यूक्रेन गैस और गेहूं उत्पादन के सर्वोच्च देश हैं। गैस सप्लाई नहीं की गई, तो यूरोप कंपकंपाया है। गेहूं की आपूर्ति नहीं हो सकी, तो गरीब, पिछड़े देशों में खाद्य-संकट उभरा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था भी गिरी है। रूस और यूक्रेन में धार्मिक, जातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक समानताएं हैं।

यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस एक साथ आए

जिनेवा

यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस एक साथ खड़े नजर आए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जी7 (अमेरिका को छोड़कर) जैसे प्रमुख देश शामिल हैं।

रूस, अमेरिका, इजरायल और हंगरी सहित 18 ने इसके खिलाफ वोट डाले। भारत, चीन और ब्राजील सहित 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बीते 3 बरसों में अमेरिका हमेशा यूरोपीय देशों के साथ मतदान करता था। यह पहली बार है जब उसने अलग रास्ता चुना है। अमेरिका में आया यह बदलाव यूरोपीय पक्ष से अलग होने का संकेत देता है। यह अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव भी दर्शाता है।

तीन साल पहले रूस के यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद यह ऐसा पहला मौका रहा, जब ने यूक्रेन की ओर से यूएन में पेश मसौदा प्रस्ताव को यूएस ने रोकने का प्रयास किया। प्रस्ताव में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैन्य वापसी, शत्रुता को समाप्त करने और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की गई है।

यूरोपीय देशों और जी7 (अमेरिका को छोड़कर) ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे यह पारित हो गया। मालूम हो कि भारत और चीन ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

प्रस्ताव पास हो जाने से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसे अपनी मंजूरी दे दी। इसमें आक्रमण के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग भी की गई है।

कुल 193 सदस्यीय विश्व निकाय में 93 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया जबकि 18 ने विरोध किया।

भारत सहित 65 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। इस निकाय के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इन्हें विश्व जनमत का संकेतक माना जाता है। पिछले प्रस्तावों में 140 से अधिक देशों ने रूस की आक्रामकता की निंदा की थी। चार यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे को हटाने की मांग की गई थी।

न्यूज ब्रीफ

ट्रंप प्रशासन कर रहा कर्मचारियों की छंटनी, अमेरिका में हो रही आलोचना

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सरकारी कर्मचारियों के बुरे दिन शुरू हो गए। बड़ी संख्या में

सरकारी कर्मचारियों ने रिटायरमेंट ले लिया है। वहीं कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। इसके अलावा एलन मस्क ने कहा है कि जो भी कर्मचारी अपनी वर्क रिपोर्ट नहीं भेजेंगे उनका भी इस्तीफा मान लिया जाएगा। ट्रंप ने मस्क को कॉस्ट कटिंग की जिम्मेदारी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डॉज) के हेड एलन मस्क के इस कदम की अमेरिका में आलोचना हो रही है। ट्रंप और मस्क पहले नहीं हैं जो अमेरिका में इस तरह कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। 30 साल पहले बिल क्लिंटन और उनके सहयोगी उपराष्ट्रपति अल्बर्ट गोर ने भी यह रणनीति बनाई थी और उसे लागू भी किया था। उस समय की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हटाकर अरबों डॉलर की बचत की थी। क्लिंटन के समय में इस प्लान में भूमिका निभाने वाले लोगों का कहना है कि वह इससे बहुत अलग था। उस समय किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई थी और अरबों डॉलर की बचत भी की गई थी। उन्होंने कहा कि एलन मस्क की तरह अचनाक किसी से नौकरी छोड़ने का नहीं कहा गया था। सरकारी कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी और इस काम में कई साल लगे थे। जानकार लोगों का कहना है कि बिल क्लिंटन ने बिना किसी संवैधानिक संकट के काम किया था। उन्होंने छंटनी नहीं की बल्कि लोगों पर ही फैसला छोड़ दिया था, लेकिन इस सरकार का लक्ष्य केवल नौकरियां खत्म करना है। हमारा लक्ष्य काम को अच्छा करना और कम कीमत में ज्यादा काम करवाना था। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया था। ऐसे में नौकरियां बढ़ गई थीं। इसके अलावा तकनीक का सहारा लिया और काम को आसान बनाया था।

ऑनलाइन चैलेंज के चक्कर में किशोर की मौत

ब्राजीलिया। ब्राजील में एक 14 साल के किशोर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यह लड़का एक ऑनलाइन चैलेंज के चक्कर में खुद को अजीब तरह का इंजेक्शन लगा बैठा, जिसके कारण उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। अस्पताल में एक हफ्ते तक इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। डावी न्यून्स मोराइरा नाम के इस लड़के को अचानक उल्टियां होने लगीं और वह लड़खड़ाने लगा, जिसके बाद उसके पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जांच के दौरान पता चला कि उसने अपने शरीर में एक ऐसा तरल पदार्थ इंजेक्ट किया था, जिसमें जली हुई तितली की राख मिलाई गई थी। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और तत्काल उसकी हालत सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। लड़के को ब्राजील के विटोरिया दा कोनक्विस्टा जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ उसकी जान बचाने में जुटे रहे। लेकिन सात दिन तक चले इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः उसने दम तोड़ दिया।

बांग्लादेश के वायु सेना अड्डे पर हमला, कारोबारी की मौत, वायुसेना अड्डे पर सेना ने संभाला मोर्चा

ढाका। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में वायु सेना अड्डे पर कुछ बदमाशों मे

हमला किया है, इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बांग्लादेश की सेना ने इसकी पुष्टि कर बताया कि वायुसेना अड्डे पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सूत्रों के अनुसार, मृतक की पहचान 30 वर्षीय व्यापारी शिहाब कबीर के रूप में की गई है, जिसकी कथित तौर पर गोली मारकर हत्या की गई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासन संभालने के बाद यह पहला ऐसा हमला है। सेना ने वायुसेना अड्डे पर मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के जनसंपर्क प्रभाग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा, समिति पारा के कुछ अपराधियों ने कॉक्स बाजार स्थित वायुसेना अड्डे पर हमला बोल दिया। बांग्लादेश वायुसेना इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रही है। बताया जा रहा हैं कि यह हमला एक भूमि विवाद के कुछ घंटों बाद हुआ, इसके कारण वायुसेना कर्मियों और निवासियों के बीच टकराव हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉक्स बाजार के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने भी पुष्टि की कि स्थानीय लोगों और वायु सेना के जवानों के बीच झड़प हुई है। सलाहुद्दीन ने कहा कि इस झड़प के कारणों की जांच दोनों पक्षों से बातचीत के होगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पाकिस्तान में वकीलों और पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के वकीलों और पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पेका) में किए गए संशोधनों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की सोमवार को बुलाई गई सलाहकार सभा में स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया।

खबर के अनुसार, बैठक में सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। बैठक में मौजूद पत्रकारों और वकीलों ने पेका (संशोधन) अधिनियम, 2025 की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना। यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि पेका (संशोधन) अधिनियम, 2025, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित मीडिया कर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार को याद दिलाया गया है कि इस संधि पर पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह संशोधन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। बैठक में डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ती सेंसरशिप पर चिंता व्यक्त की गई।

एससीबीए की ओर से बैठक में इसके अध्यक्ष मियां मोहम्मद रऊफ अत्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद इशाक नोटजई, बलूचिस्तान के उपाध्यक्ष मोहम्मद औरंगजेब खान, कार्यवाहक सचिव चौधरी तनवीर अख्तर, वित्त सचिव मुनीर अहमद मलिक, आयशा मलिक, हमूद उर रहमान अवान, बलूचिस्तान बार काउंसिल के सदस्य खलील पानेजई और हाफिज अहसान खोखर ने हिस्सा लिया। मीडिया की ओर से बैठक में मुनीजा जहांगीर, अरशद अंसारी, अफजल बट, जाहिद हसन, हामिद मीर, मजहर अब्बास, आरिफा नूर और अन्य शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि सिंध हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पेका) में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती दी गई है।

युद्ध के 3 सालः 475000 मौतें, 63 लाख लोगों ने छोड़े घर

वॉशिंगटन। रूस यूक्रेन युद्ध को तीन साल हो गए हैं। युद्ध के चलते अब तक 475000 मौतें हुईं हैं और 63 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इन तीन साल होने पर 267 ड्रोन से एक साथ हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, खार्किव, पोल्टावा, सुमी, कीव, चेर्निहाइव, मायकोलाइव और ओडेसा सहित पूरे यूक्रेन में कम से कम 13 क्षेत्रों में ड्रोन रोके गए। यह अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है।यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं। 24

फरवरी इस युद्ध को तीन साल पूरे हो गए हैं। तीन साल होने के बाद भी यह युद्ध नहीं रुक पाया है। युद्ध रोकने के लिए सऊदी अरब में अमेरिका ने रूस के साथ मीटिंग की, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात रही कि इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी की शुरुआत में कहा था कि इस युद्ध के कारण 45,000 सैनिक मारे गए। वहीं उन्होंने दावा किया कि 390,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। इन आंकड़ों की मानें तो अब तक दोनों तरफ से 4 लाख 75 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में रूस की ओर से उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी लड़ते हुए देखा गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्सक इलाके पर हमला किया है। यहीं पर उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ रहे थे। उत्तर कोरियाई सैनिकों के भी बड़ी संख्या में मारे जाने की खबर है। लेकिन अब वह पीछे हट चुके हैं।

चाबहार पर ट्रंप के आदेश से भारत को नुकसान तो चीन को हो सकता है फायदा

भारत ने इसके विकास और संचालन के लिए ईरान के साथ किया है समझौता

तेहरान

ईरान के चाबहार पोर्ट पर ट्रंप के कदम के बाद भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इस महीने 6 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चाबहार पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करने या संशोधित करने का निर्देश दिया था। चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया तक पहुंच हासिल करने के भारत के अभियान के लिए अहम है। बीते साल भारत ने इसके विकास और संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

अमेरिका के कदम ने एक तरफ जहां भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, वहीं प्रतिद्वंद्वी चीन के लिए यह मौके है। चीन ने इस इलाके में पाकिस्तान के ग्वादर में स्थित बंदरगाह में बड़ा निवेश किया है। इससे न सिर्फ चीन को व्यापार बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में पैर जमाने का रास्ता साफ हो सकता है, जहां भारत का लंबे समय से रणनीति प्रभाव रहा है, लेकिन चीन का ग्वादर प्रोजेक्ट एक तरह अभी तक असफल रहा है, जबकि भारत के बनाए चाबहार ने व्यापार शुरू कर दिया है। ट्रंप के आदेश का उद्देश्य ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना है, लेकिन इससे भारत के प्रमुख रणनीतिक हितों पर भी असर पड़ेगा।

इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने साल 2024 में चाबहार डील की थी।

आईपीजीएल ने पहली बार 2018 में पोर्ट का संचालन संभाला और तब से 90 हजार से ज्यादा टियुस के कंटेनर ट्रैफिक और 84 लाख से ज्यादा के थोक और सामान्य कार्गो को संभाला है।

भारत के लिए इस पोर्ट का महत्व आर्थिक से ज्यादा है। यह एक रणनीतिक संपत्ति है, जो ऐतिहासिक रूप से अस्थिर पड़ोसी क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। साथ ही दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है।

ट्रंप के आदेश से भारत की रणनीतिक स्थिति के कमजोर होने का खतरा है। छूट खत्म करने के फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वास्तव में प्रतिबंधों को छूट रद्द करने से भारत अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। यह मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम कर सकता है। छूट को रद्द करने का नकारात्मक असर क्वाड पर पड़ सकता है।

दक्षिण कोरिया में निर्माणाधीन पुल ढहा, तीन की मौत, सात घायल

दक्षिण कोरिया में मंगलवार सुबह लगभग 9ः 49 बजे एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। यह हादसा चुंगचेओंग प्रांत के चेओनान के पास सियोल-सेजोंग राजमार्ग पर हुआ। हादसे में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। सियोल-सेजोंग राजमार्ग पर निर्माण के दौरान पुल के लिए तैयार किए गए 50 मीटर लंबे पांच स्टील सपोर्ट ढह गए। गंभीर रूप से घायल सात लोगों में से एक को कार्डियक अरेस्ट हुआ। अग्निशमन अधिकारियों का मानना है कि कई कर्मचारी मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है।

ईरान से तेल व्यापार करने के चलते अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

वॉशिंगटन

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यह कदम ईरान पर दवाब बनाने के लिए लगाए हैं।

अमेरिका की ओर से यह फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने क लिए उठाया गया है। जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। यह नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि, तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्तपोषण को रोक पाएगा।

सोमवार को अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से कथित जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जिनमें से चार भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉसमॉस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी हैं।

बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों को चिह्नित किया है और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने, वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ मिलकर, 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए तथा ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है।

चिंतित चीनी सरकार, लड़कियां नहीं तीन करोड़ पुरुष अविवाहित

बीजिंग

चीन में हाल ही में संपन्न हुई जनगणना से खुलासा हुआ है कि देश में करीब तीन करोड़ पुरुष अविवाहित हैं। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से कही ज्यादा है। इस असंतुलन का प्रमुख कारण दशकों से समाज में लड़कों को प्राथमिकता देना है। हालांकि, हाल के वर्षों में लड़कियों के जन्म में मामूली वृद्धि हुई है, फिर भी लिंगानुपात में भारी अंतर बना हुआ है।

सातवीं जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, बीते वर्ष चीन में 1.2 करोड़ शिशुओं का जन्म हुआ, इसमें प्रति 100 लड़कियों पर 111.3 लड़कों का अनुपात दर्ज हुआ। वर्ष 2010 में यह अनुपात 118.1 था, जिससे मामूली सुधार का संकेत मिलता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार भी विवाह योग्य पुरुषों की बढ़ती संख्या की समस्या को हल करने में नाकाफी है। इस बारे में जानकार ने बताया कि चीन में आम तौर पर पुरुष अपने से कम उम्र की महिलाओं से विवाह करते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति को देखते हुए, अधिक उम्र के कुंवारे पुरुषों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में भारी कमी दर्ज हुई है, जो भविष्य में और भी जटिल सामाजिक चुनौतियों को जन्म दे सकती है। जानकार ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में विवाह योग्य लड़कों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ विवाह योग्य लड़कियों की कमी एक गंभीर समस्या बन सकती है। चीन में लिंगानुपात का यह असंतुलन भविष्य में विवाह, परिवार संरचना और समाज के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत बदलाव और समाज में लिंग समानता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

करांची में कॉलेज परिसर में होली मनाने पर छात्रों को नोटिस जारीए संस्थान ने कहा-यह पुराना मामला, प्राथमिकी दर्ज होने की खबर को किया खारिज

करांची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के करांची में स्थित एक प्रमुख निजी विश्वविद्यालय को अपने परिसर में होली मनाने पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा। छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को परिसर के नियमों की उल्लंघन करार दिया जा रहा था। पूर्व सांसद लाल मल्ही ने सोशल मीडिया पर दाऊद इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को जारी नोटिस पोस्ट किया है। संस्थान ने

साफ कहा है कि यह एक पुराना मामला है और इसने छात्रों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज होने की खबरों को खारिज कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि छात्रों को प्रशासन से मंजूरी लिए बिना परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नोटिस जारी किया था, जो विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने पहले ही नोटिस का जवाब दे दिया है। लाल मल्ही ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बढ़ते रोध पर चिंता व्यक्त करते हुए सवाल किया कि क्या होली मनाना अपराध है पिछले साल भी हिंदू छात्रों को होली के त्योहार के दौरान कुछ अन्य प्रांतों में भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था।

सैनिक बार्डर पर तो परिवार की सुरक्षा जरूरी : हाईकोर्ट

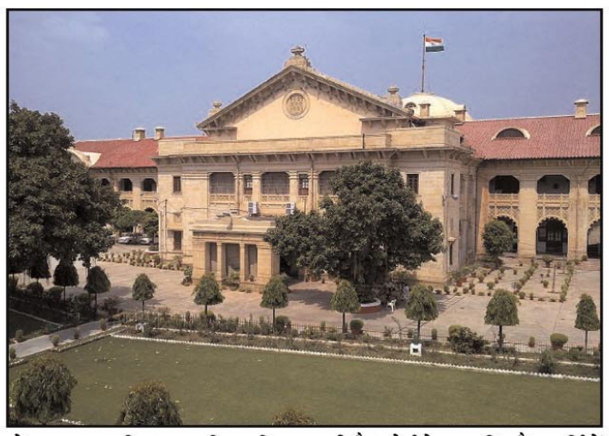

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के परिवार की सुरक्षा शिकायतों पर ऐक्शन के लिए राज्य सरकार की प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटी को मंजूरी दे दी है और कमेटी को अगले एक माह में बैठक करने का निर्देश दिया है। राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। जिसमें विभिन्न विभागों,तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कमेटी की बैठक का कोरम पचास फीसदी होगा और नियमित बैठक होती रहेगी। कमेटी सैनिक परिवार की सुरक्षा शिकायतों पर निर्णय लेकर कार्रवाई करेगी। हर बैठक में सेना के कम-से-कम एक प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसी तरह से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर तैनात सैन्यकर्मी की फिरोजाबाद की सहायक अध्यापिका पत्नी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य को सैन्यकर्मियों के परिवारों से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पीड़ितों को कभी भी असहाय या असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक शिक्षा मित्र पर सैन्यकर्मी की पत्नी को परेशान करने की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।सेना अधिकारी के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।तो पत्नी ने हाईकोर्ट की शरण ली। केवल आरोपी शिक्षामित्र का स्थानांतरण कर दिया गया लेकिन उसने दोबारा स्कूल में आकर अशोभनीय हरकत की। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि राज्य के अधिकारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे हैं और इससे याची के पति की राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने कहा कि सैन्यकर्मियों के परिवार की शिकायत का प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और एक जवाबदेही प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। कोर्ट ने कई सुझाए दिये और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।जिसपर राज्य सरकार की तरफ से राज्य व जिला स्तर की कमेटी गठित होने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने कमेटी में कुछ बदलाव भी किए।और अधिक जवाबदेह बनाया।

बजट सत्र : सपा सरकार में हर काम को समाजवादी नाम दिया जाता था, जबकि पैसा सरकारी होता था : सीएम योगी

लखनऊ, (हि. स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नए सामर्थ्य की चर्चा की। उन्होंने कुम्भ पर सवाल खड़ा करने वाले विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। कहा कि कि कुंभ ने प्रदेश में पंच तीर्थ बना दिये। समाजवादी पार्टी के समय योजनाओं का नाम समाजवादी हो गया था। आज हर प्रदेश वासियों को बिना भेदभाव लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों को दीनदयाल स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल स्टाफ नियुक्त हैं। स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में ब्लड बैंक की स्थापना, तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। एसजीपीजीआई में मेडिकल स्टाफ की नियुक्तिां की गई हैं। हमारी सरकार ने एसजीपीजीआई में आठ ब्लॉक बनवाये, 1200 बेड के अस्पताल के रूप में कार्य हो रहा है। सदन में एक परिपाटी चल गई है कि राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना। इस तरह हम संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान का भी यह अनादर है। सीएम योगी ने कहा कि हम अपनी बातों को शिष्ट आचरण से भी कह सकते हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी का व्यवहार और आचरण लोकतांत्रिक भी नहीं था। समाजवादी पार्टी का आचरण सभी ने सदन ने देखा ।महामहिम ने इस सदी के सबसे बड़े उत्सव महाकुम्भ की बात कही। इस समय तक अब तक 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था का स्नान कर चुके हैं। यह आयोजन बिना भेदभाव एक स्थान पर आमजन मानस को एकत्र कर सकता है। इसको दुनिया ने देखा। जब गौरव की अनुभूति करनी चाहिए तो सपा के सदस्य छींटाकशी कर रहे हैं। अयोध्या को लेकर हमारे विरोधी उपहास उड़ाते

थे, लेकिन हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास था। राममंदिर आंदोलन में ये लोग हर तरह से रोड़े अटकाने लगे। जब मंदिर बन गया तो ये लोग कहने लगे ..'राम तो सबके हैं'। इसी तरह महाकुंभ को लेकर भी कहते थे। इस बार हमारा पूरा मंत्रिमंडल वहां गया और विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से इसका उपहास उड़ाती थी। कहती थी क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे ? क्या व्यवस्था हो जाएगी? ये लोग पहले उपहास उड़ाते हैं, फिर स्वीकार भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी खुद गए और स्नान कर आये। इसी तरह नेता विरोधी दल अब कहने लगे कि पहले सनातनी हैं, फिर समाजवादी।

महाकुंभ ने प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिये – मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज के साथ ही काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से पहुंच रहे हैं। अयोध्या- काशी में 52 दिनों में अपार श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा बताया कि मक्का में 24 दिन में एक करोड़ 40 लाख, वेटिकन सिटी में 80 लाख, जबकि अयोध्या में इसका 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे। यह उत्तर प्रदेश के नया सामर्थ्य दिखाता है। 2025 सारे आंकड़ो को ध्वस्त करने जा रहा है।सनातन की सुंदरता वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुँचने में परेशानी नजर आ गई। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल लगातार दुष्प्रचार करता रहा कि बस्ती, गोरखपुर मंडल के 35 लोग मारे गए। जबकि बाद में पता चला वो लोग अपने घर पहुंच गए। इसी तरह प्रयागराज के खूंटी गुरु की भी कहानी हुई। संसद में एक सज्जन कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, जबकि डिजिटल कुंभ की वजह से 28 हजार लापता लोग वापस मिल गए। योगी ने कहा कि ये लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से ही लड़ने लगते हैं। स्वार्थ के लिए संविधान को लेकर लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के अक्षयवट कॉरिडोर को इनके नेता अकबर का किला कहते हैं। अक्षयवट वेदों में वर्णित है। अकबर का कार्यकाल कब हुआ। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज मे 200 से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ। सिंगल लेन से 2 लेन, 4 लेन,14 फ्लाईओवर बनाये गए। बेहतर कनेक्टिविटी की गई, जो आया वो बेहतर व्यवस्था से प्रसन्न होकर गया। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति संवेदना भी है। इस पर राजनीति नही होनी चाहिए।

प्रशासन ने आगामी त्योहारों के लिए कसी कमर, जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

जालौन, (हि.स.)। आगामी दिनों में महाशिवरात्रि, रमजान, नवरोज, होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, ईद-उल-फितर, चैत्र नवरात्रि और श्रीराम नवमी जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मंगलवार को विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक, शिव बारात और शोभायात्रा के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और सभी शोभायात्राओं में झांकी, पताका और ध्वज मानक आकार के अनुसार होने चाहिए। इसके साथ ही, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीजे की ध्वनि सीमा निर्धारित स्तर पर ही रखी जाएगी ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। जुलूस के दौरान बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी जगह लटके या जर्जर तारों की वजह से कोई दुर्घटना न हो। होली त्योहार को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि होलिका दहन स्थल का निरीक्षण कर लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दहन बिजली के तारों के नीचे या मुख्य सड़कों पर न किया जाए। होली के दौरान शराब की दुकानों की जांच और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं मद्यनिषेध विभाग को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

मुलायम सिंह यादव के नाम पर सदन में जो हुआ, नहीं होना चाहिए था : सतीश महाना

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल विधानसभा में मुलायम सिंह यादव के नाम पर सदन में जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। विधानसभा चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की भी है और विपक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी है। बता दें कि, सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेता जी मुलायम सिंह का सम्मान करते हो, हर बात मानते हो तो क्या यह भी मानोगें कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस टिप्पणी के बाद सदन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और जिसमें स्पीकर सतीश महाना को सख्त रूख अपनाना पड़ा था।

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की सीबीआई जांच के निर्देश

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिल्डरों, कंसोर्टियम और नोएडा अधिकारियों के खिलाफ घर खरीदारों के पैसे हड़पने, नोएडा के अधिकारियों, डेवलपर्स और घोटाले से जुड़े अन्य व्यक्तियों सहित सभी शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। आदेश में पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार की एक पाठ्यपुस्तक का विशेष उदाहरण बताया। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने नोएडा में चार स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में से तीन को कवर करते हुए दस अलग-अलग निर्णय दिए। इसमें प्रमुख डेवलपर्स और कंसोर्टियम हिस्सेदारों दोनों की जवाबदेही को ठहराया गया है। कोर्ट ने लैंड यूज वायलेशन, वित्तीय अनियमितता, दिवालिया कार्यवाही और स्पोर्ट्स सुविधाओं के पूरा न होने सहित कई अन्य पहलुओं की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उसके पास जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोर्ट ने पाया कि नोएडा से महत्वपूर्ण लाभ और रियायतें लेने के बाद भी डेवलपर्स ने अनिवार्य खेल सुविधाओं को बनाने की बजाय केवल व्यवसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ये ऑर्डर सेक्टर 78, 79 और 101 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं से संबंधित हैं। सेक्टर 150 में दो स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाएं जिसे लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन द्वारा विकसित की गईं। वहीं सेक्टर 78-79 में परियोजनाओं के प्रमुख डेवलपर्स और लॉजिक्स की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना वर्तमान में दिवालियेपन की कार्यवाही से गुजर रही है। कोर्ट ने इसे वित्तीय और कानूनी दायित्वों से बचने के लिए एक जानबूझकर रणनीति करार दिया। स्पोर्टस सिटी के प्रमुख डेवलपर्स ने याचिका के माध्यम से नोएडा द्वारा की जा रही कार्रवाई से बचने की मांग कोर्ट से की थी। हाइकोर्ट ने उनके दावों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि डेवलपर्स मूल योजना के अनुसार परियोजना का निर्माण नहीं कर सके।

राष्ट्र निर्माण में एनसीसी और एनएसएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : राज्यपाल

रांची, (हि.स.)। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संगठन युवाओं को सामाजिक सेवा, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की दिशा में प्रेरित करते हैं। रक्तदान, साक्षरता अभियान, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में इनकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही है। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस शिविर-2025 में झारखंड राज्य का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये बधाई देते हुए बोल रहे थे। उन्होंने एनसीसी से अपने जुड़ाव का स्मरण करते हुए कहा कि छात्र जीवन में उनका भी एनसीसी से गहरा नाता रहा है और सैन्य सेवा की ओर उनका झुकाव था। हालांकि आपातकाल के दौरान जेल जाने के बाद उनका जीवन एक नया मोड़ ले लिया और वे राजनीति में सक्रिय हो गए। बरेली की जनता के स्नेह से वे आठ बार लोकसभा सांसद चुने गए और अब झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए एनसीसी और एनएसएस में बेटियों की बढ़-चढ़कर भागीदारी को एक उज्ज्वल उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां आज अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से देश और समाज को नई दिशा दे रही हैं, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'युवा शक्ति, विकसित भारत' के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि एनसीसी और एनएसएस देश की विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां भारत के विभिन्न राज्यों के छात्र-छात्राएं एकजुट होकर अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व की भावना का विकास करते हैं। राज्यपाल ने झारखंड राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को एनसीसी और एनएसएस से जुड़ने का आह्वान किया ताकि वे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, एनसीसी के एडीजी, बिहार-झारखंड मेजर जनरल एएस बजाज, एनसीसी के वरीय पदाधिकारी, एनएसएस के समन्वयक, एनसीसी के कैडेट्स एवं एनएसएस के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया

लोहरदगा, (हि.स.)। लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड में मंगलवार को झारखंड राज्य जलछाजन मिशन योजना ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी भगत, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप शेखावत द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जीप अध्यक्ष रीना कुमारी भगत ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसान सरकार को योजना में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने अपने घर और गांव में योजनाओं का चुनाव करें। इसके तहत मेढ़ बंधी, तालाब निर्माण, डोभा निर्माण मेढ़ में वृक्षारोपण और कृषि की नई तकनीक अपनाकर अपनी आजीविका को अपनाए और जीवन मे आगे बढ़े। आज कई ऐसे किसान हैं जो परंपरागत खेती से हटकर एस्ट्रॉबेरी, गन्ना, फूल जैसे खेती अपना कर आगे बढ़ रहे हैं। इसे हर किसान को अपनाने की जरूरत है। उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप शेखावत ने कहा कि हमारा जिला ग्रामीण जिला है और यहां निवास करने वाले किसान हैं। ऐसे में जरूरत है कि पानी का रख रखाव करते है। कम पानी मे ज्यादा कृषि की तकनीक पर ध्यान दिया जाए। आज जिन किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे किसानों से भी सीखने की जरूरत है। हर किसान की जिम्मेवारी है कि इस योजना को सफल बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है वह पूरा हो सके। कार्यक्रम मे सभी अतिथियों की ओर से अलग अलग विभाग के जरिए लगाए गए स्टाल का निरीक्षण करते हुए पपीता, ओल, अमरूद, गेहूं, सरसों इत्यादि उत्पाद का बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में फीता, गमला व छोटा फुहारा मशीन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा प्रखण्ड परिसर में पौधारोपण किया गया। मेढबन्धी को लेकर भूमि पूजन किया गया तथा अतिथियों द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर बडी संख्या में लोग मौजूद थे।

भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास को ढहाने के मामले पर बोला हमला, उठाए सवाल

रांची, (हि.स.)। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार दिल्ली की पूर्व सरकार से बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध भी अति मधुर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए शीश महल बनाना शुरू किया था। अब सूचनाओं आ रही हैं कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री सोरेन इसी का अनुसरण करने जा रहे हैं। आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास जिसमें पिछले ढाई दशकों में अनेक मुख्यमंत्री ने निवास किया, उसको भवन निर्माण प्रमंडल-1 ने टेंडर निकालकर जमींदोज कर दिया है। पूरे तरीके से भवन को ढहाने का काम जारी है। यह ऐतिहासिक धरोहर है क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर अनेक मुख्यमंत्री ने यहां निवास किया था। प्रतुल शाह देव ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा कि अब विभाग की लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं ताकि नए भवन का डीपीआर बन सके। जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली के शीश महल की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक सभी आधुनिक सुख सुविधा से लैस शीश महल बनाने पर चर्चा चल रही है। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान मंदिर की भव्यता पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतुल ने कहा कि जिस प्रदेश में डेढ़ वर्षों में एक भी अबुआ आवास का गृह प्रवेश नहीं हुआ। जहां आज भी बड़ी संख्या में लोगों के सर पर छत नहीं है। ऐसे राज्य में इस तरह की अगर फिजूल खर्ची करने की सोची जा रही है तो यह प्रदेश के आदिवासी मूल निवासी जनता के साथ क्रूर मजाक होगा। प्रतुल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी गठबंधन से मांग की कि वो रांची में बनने वाले शीश महल को लेकर स्थिति स्पष्ट करें।

महाशिवरात्रि को लेकर जिले के शिवालय में तैयारी जोरों पर, 69 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति

अररिया, (हि.स.)। महाशिवरात्रि को लेकर जिले के सभी शिवालयों और मंदिरों में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शिवालय सहित मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। कुसाकांटा के सुन्दरनाथ धाम मंदिर, मदनपुर में मदनेश्वरधाम, रानीगंज के बसेटी स्थित इन्द्रमतेश्वरधाम, फारबिसगंज के बड़ा शिवालय, शंकरपुर के शिव मंदिर, जोगबनी के शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा अर्चना को लेकर परिसर में साफ सफाई, रंग रोगन के साथ ही फूलमालाओं से सजाया संवारा जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों और शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारी की है। जिला प्रशासन की ओर से 69 स्थानों को चिन्हित कर वहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की है।इसके अलावे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति को लेकर डीएम अनिल कुमार और एसपी अंजनी कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश निकाला गया है। डीजे सहित द्विअर्थी गीतों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।साथ ही विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम के साथ ही अररिया सदर और फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमंडल प्रशासन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंदिर और शिवालय सहित मौके पर लगने वाले मेला स्थल पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी किए जाने का निर्देश दिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर खासकर कुसाकांटा के सुन्दरनाथ धाम मंदिर, मदनपुर स्थित मदनेश्वरनाथ धाम मंदिर, रानीगंज के बसेटी स्थित इन्द्रमतेश्वरधाम मंदिर, फारबिसगंज के बड़ा शिवालय, शंकरपुर शिव मंदिर में हजारों की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ती है।जिसमें अररिया जिला सहित पड़ोसी जिला और आबादी संख्या में नेपाल से शिव भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए इन मंदिरों में पहुंचते हैं।

जसीडीह-झाझा रेलखंड पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से बचीं सैकड़ों जान

पटना, (हि.स.)। बिहार में झाझा-जसीडीह रेलखंड पर बीती देर रात एक बजे रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से सैकड़ों लोगों की जान बच गई । पूर्वी रेलवे के झाझा-जसीडीह रेलखंड पर रेलवे की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने अप ट्रैक पर दो फिश प्लेटों को खुला पाया गया। रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग कर रहे कर्मचारी सूरज वर्मा और चंद्रिका यादव ने किलोमीटर संख्या 344/17-19 के पास ट्रैक की गड़बड़ी को देखा।

उन दोनों ने देखा कि एक फिश प्लेट पूरी तरह खुली हुई थी, जबकि दूसरी के नट-बोल्ट ढीले थे। उन्होंने बिना देर किए विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिससे समय रहते ट्रैक की मरम्मत की जा सकी। घटना की गंभीरता को देखते हुए 13,185 अप सियालदह-जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस को 45 मिनट तक रोका गया। इस दौरान रेलवे कर्मियों ने तेजी से ट्रैक की मरम्मत की और सुनिश्चित किया कि कोई तकनीकी दिक्कत न रहे। एईएन जसीडीह पिंटू दास ने बताया कि जांच जारी है कि फिश प्लेट प्राकृतिक रूप से खुली थी या किसी ने जानबूझकर इसे खोला था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस रेलखंड में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं।

गत 13 फरवरी 2025 को झाझा-गिद्धौर रेलखंड पर अज्ञात तत्वों ने पटरी काटने की कोशिश की थी। घोरपारन स्टेशन के पास एसएसबी ने 45 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। घटना के बाद रेलवे ने पूरे रेलखंड में सुरक्षा पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आरपीएफ को सतर्क किया गया है और कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

पटना मेडिकल कॉलेज बिहार की अमूल्य धरोहरों में से है एक : राष्ट्रपति

पटना, (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज बिहार की अमूल्य धरोहरों में से एक है। इस संस्थान का पुरातनता को संरक्षित करने और आधुनिकता की ओर निरंतर अग्रसर होने का गौरवशाली इतिहास रहा है। पटना मेडीकल कालेज एवं हास्पिटल (पीएमसीएच) एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक रहा है। इस संस्थान के पूर्व छात्रों ने अपनी प्रतिभा, सेवा और समर्पण के बल पर देश-विदेश में अपना और पीएमसीएच का नाम रोशन किया है। वह मंगलवार को पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहीं थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि इलाज के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाने से कई तरह से नुकसान होता है, जैसे इलाज में देरी, भोजन, आवास और रोजगार की समस्या। इससे बड़े शहरों के चिकित्सा संस्थानों पर भी बोझ पड़ता है। देश भर में अच्छे चिकित्सा संस्थानों का विकेंद्रीकरण इन सभी समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर जैसे शहर विशिष्ट उपचार के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। बिहार को भी ऐसे कई केंद्र विकसित करने चाहिए। इससे न केवल बिहार के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच और इसके पूर्व छात्र अपने अनुभव से इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह तकनीक का युग है। चिकित्सा क्षेत्र में भी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें चिकित्सा प्रक्रिया को सरल और सटीक बना रही हैं। उन्होंने पीएमसीएच के सभी हितधारकों से नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया। कहा कि इससे न केवल इलाज आसान होगा, बल्कि डॉक्टरों का ज्ञान और दक्षता भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे डाक्ट शोधकर्ता, चिकित्सक, शिक्षक और परामर्शदाता भी हैं। इन सभी भूमिकाओं में वे लोगों और समाज की सेवा करते हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। उन्होंने उनसे लोगों को रक्त और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया।

सर्राफा बाजार में तेजी, सोना 88 हजार पार

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में तेजी का रुख है। इस तेजी के कारण देश के कई हिस्सों में 24 कैरेट सोना 88 हजार रुपये के स्तर को पार कर गया। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 87,880 रुपये से लेकर 88,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है।

इसी तरह 22 कैरेट सोना 80,550 रुपये से लेकर 80,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी 600 रुपये की तेजी आई है। इस तेजी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही कारोबार कर रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 88,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 80,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 87,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 80,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 87,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 80,600 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 87,880 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 80,550 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 87,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 80,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 88,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 80,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। वहीं पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 87,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 80,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 88,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 80,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 87,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 80,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

कई कंपनियां अपनी मोटरसाइकिल पर दे रही हैं बड़े डिस्काउंट

नई दिल्ली। कई कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर बड़े डिस्काउंट दे रही हैं। इसी क्रम में मोटो मोरिनी ने अपनी लोकप्रिय बाइक सेइमेज्जो 650 स्क्रैम्बलर की कीमत में 1.90 लाख रुपये की भारी कटौती की है। इस कटौती के बाद बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत 5.20 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 7.10 लाख रुपये थी। हालांकि, इस डिस्काउंट के बावजूद बाइक के डिजाइन और मैकेनिक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 649सीसी, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो 54बीएचपी की पावर और 54 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार मिड-रेंज और हाई रिफाइनमेंट लेवल के लिए जाना जाता है। बाइक को मजबूत ट्यूबलर फ्रेम पर बनाया गया है और इसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। सेइमेज्जो 650 स्क्रैम्बलर में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील दिया गया है। इसके अन्य फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुल-एलईडी लाइटिंग, स्विचेबल डुअल-चैनल एबीएस और 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड बियर 650 से होगा।

रिलायंस असम में 50,000 करोड़ का निवेश करेगी: अंबानी

गुवाहाटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मंगलवार को कहा कि उनकी कंपनी ने अगले पांच वर्ष में असम में पांच अलग-अलग क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। एडवांटेज असम व्यापार शिखर सम्मेलन में अंबानी ने कहा कि यह पैसा असम को प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए तैयार करने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 के निवेश शिखर सम्मेलन में मैंने 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। तब से निवेश 12,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। यह राशि चौगुनी हो जाएगी और हम अगले पांच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। अंबानी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग किया जाएगा, उनमें हरित व परमाणु ऊर्जा, खाद्य व गैर-खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला और रिलायंस के खुदरा स्टोर का विस्तार शामिल है।

केटीएम में 1,360 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी बजाज ऑटो

नई दिल्ली। यूरोपीय मोटरसाइकिल ब्रांड केटीएम में स्वदेशी कंपनी बजाज ऑटो करीब 1,360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बना रही है। यह कंपनी केटीएम मोटरसाइकिलों के मालिक पियरर मोबिलिटी एजी के करीब 75 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करती है। बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी ऑस्ट्रिया में पियरर बजाज एजी (पीबीएजी) में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है। नवंबर 2024 में केटीएम ने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी और इमरजेंसी फंड की जरूरत बताई थी। अब बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने केटीएम में 150 मिलियन यूरो (करीब 1,360 करोड़ रुपये) के निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे संभावना बढ़ गई है कि यह फंड यूरोप में केटीएम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस निवेश के बाद बजाज केटीएम का सबसे बड़ा शेयरधारक बनेगा या नहीं। बजाज ऑटो और केटीएम के बीच वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का गठजोड़ रहा है। भारत में केटीएम ब्रांड की निरंतर उपस्थिति के लिए यह सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा है। 1992 में स्टीफन पियरर ने केटीएम का अधिग्रहण किया था, जब यह कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी। 2007 में बजाज ऑटो ने केटीएम में निवेश किया और 14.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। बाद में बजाज ने केटीएम के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई और दोनों कंपनियों के बीच कई मैन्युफैक्चरिंग समझौते हुए।

यूएस टैरिफ में बढ़ोतरी से सबसे अधिक भारत, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड होंगे प्रभावित

भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाएं अधिक उन्मुख हैं, जिससे इन शुल्क का असर कुछ कम होगा

वॉशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड पर होगा। एक रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी व्यापार शुल्क से एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने की संभावना में कहा कि वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं का अमेरिका के प्रति आर्थिक जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है। इसका अर्थ है कि यदि शुल्क लगाया गया तो इन पर इसका सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाएं घरेलू रूप से अधिक उन्मुख हैं, जिससे इन शुल्क का असर उन पर कुछ कम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह भारत सहित अपने व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। नया अमेरिकी प्रशासन पहले ही चीन से आयात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क और इस्पात तथा एल्यूमीनियम पर 25 प्रतिशत शुल्क लागू कर चुका है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि यह इसका अंत नहीं हो सकता। अनिश्चितता बहुत अधिक है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने साझेदार अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापार शुल्क लगाने में काफी बेबाकी दिखाई है। द्विपक्षीय वार्ता भी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाएं इसके दायरे में हैं और आर्थिक गतिविधियों के लिए जोखिम मंडरा रहा है।

भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में पिछड़ सकता है: रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्ति को लक्ष्य बनाया है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 2032 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वित्तपोषण की दर को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का आवश्यक होगा अन्यथा यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) परियोजनाओं की शुरुआत में देरी और अनिश्चितताओं के कारण पूंजी की लागत 400 आधार अंकों तक बढ़ सकती है। इससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी के मामले में भी देरी और पीपीए पर हस्ताक्षर में विलंब के कारण परेशानियां हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह सभी कारक वित्तपोषण की लागत में वृद्धि के कारण भारत के ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में पीछे ले जा सकते हैं। एक विश्लेषक ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सही वित्तपोषण जोखिमों को समझने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा में जोखिम देखने वाले कारकों के प्रति सजग रहने से ही भारत अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा।

मिड-साइज सेडान सियाज की बिक्री बंद करने की योजना

नई दिल्ली

मारुति सुजुकी लोकप्रिय मिड-साइज सेडान सियाज की बिक्री बंद करने की योजना बना रही है। कंपनी मार्च 2025 तक सियाज का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देगी और अप्रैल 2025 से इसे बाजार से हटा लिया जाएगा। हालांकि, कंपनी की ओर से अब तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मारुति सियाज को भारतीय बाजार में 2014 में लॉन्च किया गया था और यह अपनी सेगमेंट की एक किफायती और फीचर-लोडेड कार के रूप में जानी जाती थी। शुरुआती वर्षों में इस सेडान ने जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी बिक्री में गिरावट देखी गई है।

अक्टूबर 2024 में मात्र 659 यूनिट्स बिकीं, जबकि नवंबर 2024 में 597, दिसंबर 2024 में 464 और जनवरी 2025 में केवल 768 यूनिट्स ही ग्राहक खरीद सके। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय कार बाजार में इसकी मांग लगातार घट रही है। सियाज की घटती लोकप्रियता के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। साल 2020 में मारुति ने इसका डीजल वैरिएंट बंद कर दिया था, जिससे इसकी बिक्री को झटका लगा। उस समय डीजल मॉडल कुल बिक्री का 30 प्रतिशत योगदान देता था, लेकिन इसके बंद होने के बाद केवल पेट्रोल इंजन के साथ यह कार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगी। इसके अलावा, कंपनी ने 2018 के बाद कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि सेगमेंट की अन्य कारों में एडवांस्ड फीचर्स जोड़े गए। अडास टेक्नोलॉजी, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टर्बो पेट्रोल इंजन जैसी खूबियों की कमी ने भी ग्राहकों को दूसरी सेडान की ओर आकर्षित किया। वर्तमान में मारुति सियाज में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 बीएचपी की पावर और 138 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार मैनुअल वेरिएंट में 20.65 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट में 20.04 किमी/लीटर माइलेज देती है। इसकी कीमत रुपए 9.41 लाख से रुपए 12.29 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। मारुति सियाज की जगह कंपनी नई मिड-साइज सेडान लॉन्च कर सकती है।

स्टारबक्स 1100 कर्मचारियों की छंटनी करेगा

कॉफी चेन कंपनी स्टारबक्स ने वैश्विक स्तर पर 1,100 कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा कंपनी खाली पड़े सैकड़ों पदों को भी समाप्त करने की भी योजना बना रही है। कंपनी के नए चेयरमैन और सीईओ ने परिचालन को ठीक करने के लिए यह कदम उठाया है। कर्मचारियों के नाम जारी एक पत्र में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को छंटनी का सामना करना पड़ेगा, उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। कंपनी के सीईओ ने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक कुशलता से काम करना, जवाबदेही बढ़ाना, जटिलता कम करना और बेहतर एकीकरण करना है। स्टारबक्स के दुनिया भर में 16 हजार कर्मचारी हैं। कंपनी के कुछ कर्मचारी छंटनी से प्रभावित नहीं होंगे। इसमें रोस्टिंग, वेयरहाउस, कंपनी के स्टोर्स में काम करने वाले बैरिस्टा कर्मचारी शामिल हैं।

एसयूवी बीई6 और एक्सईवी 9ई को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

नई दिल्ली

हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा की एसयूवी बीई6 और एक्सईवी 9ई को ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यही वजह है कि कंपनी की सेल्स और मार्केट शेयर में बड़ा उछाल देखा गया।

अब महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप में एक्सईवी 7ई नामक एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 2025 के मध्य या इसी साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है। एक्सईवी 7ई का डिजाइन एक्सयूवी.ई8 कॉन्सेप्ट से प्रेरित होगा, लेकिन इसकी रूफलाइन एक्सईवी 9ई से अलग होगी। यह तीन-पंक्ति वाली विशाल एसयूवी होगी, जिसका लुक एक्सयूवी700 के आईसीई वर्जन से मेल खाता नजर आएगा। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इसके अलावा, लेवल 2 अडास प्लस, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और वेंटिलेटेड सीटें जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी दी जाएंगी।

महिंद्रा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 59 केडब्ल्यूएच और 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ पेश कर सकती है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 500किमी से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगी। हाई-डेनसिटी एलएफपी बैटरी सेल के कारण यह ज्यादा टिकाऊ और कुशल होगी। कंपनी फिलहाल बीई 6 और एक्सईवी 9ई की बढ़ती मांग को पूरा करने पर ध्यान दे रही है, जिन्हें महज एक दिन में 30,000 से अधिक बुकिंग मिली थीं।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में कमजोरी का रुख बना हुआ है।

टेक शेयरों में दबाव बढ़ जाने की वजह से अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट का शिकार हो गए। डाउ जॉन्स ऊपरी स्तर से करीब 250 अंक टूट गया। इसी तरह एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,983.27 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 236.74 अंक यानी 1.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 19,287.27 अंक के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 127.72 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की मजबूती के साथ 43,588.93 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.39 अंक की सांकेतिक कमजोरी के साथ 8,658.98 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.79 प्रतिशत लुढ़क कर 8,090.99 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। दूसरी ओर, डीएएक्स इंडेक्स 138.37 अंक यानी 0.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,425.93 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में भी दबाव बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 8 के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक सूचकांक मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में है। एशियाई बाजारों में इकलौता गिफ्ट निफ्टी 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,613.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,923.47 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 145.28 अंक यानी 0.63 प्रतिशत टूट कर 23,196.33 अंक के स्तर तक गिर गया है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल ये सूचकांक 136.10 अंक यानी 2.02 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,613.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 1.55 प्रतिशत लुढ़क कर 1,216.67 अंक तक गिर गया है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 452.31 अंक यानी 1.17 प्रतिशत फिसल कर 38,324.63 अंक के स्तर पर, ताइवान वेटेड इंडेक्स 247.27 अंक यानी 1.05 प्रतिशत टूट कर 23,318.04 अंक के स्तर पर, कोस्पी इंडेक्स 0.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,638.13 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,368.24 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

शरवरी वाघ पहुंची अटारी-वाघा बॉर्डर, मनाया जश्न

मुंबई (ईएमएस) हाल ही में अभिनेत्री शरवरी वाघ अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंची। यहां एक्ट्रेस ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में हिस्सा लिया। शरवरी ने न सिर्फ बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, बल्कि उनके त्याग और अनुशासन की स-राहना भी की। इस दौरान उन्होंने सीमा पर होने वाले इस जोश से भरपूर देशभक्ति समारोह को देखा और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने समारोह के बाद अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और इस यादगार पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अभिनेत्री ने हॉलीवुड की मशहूर लेखिका और प्रोड्यूसर मिंडी कलिंग को वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने पर बधाई दी। शरवरी ने मिंडी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रतिष्ठित, प्रेरणादायक और अविश्वसनीय मिंडी कलिंग, बधाई! शरवरी ने अपने करियर की शुरूआत 2015 में फिल्म निमार्ता लव रंजन और संजय लीला भंसाली के साथ सहायक निर्देशक के रूप में की थी। उन्होंने बतौर अभिनेत्री 2020 में कबीर खान की द फॉरगॉटन आर्मी - आजादी के लिए से डेब्यू किया। हाल ही में वह मुंज्या में बेला की भूमिका में नजर आईं, जिसे दर्शकों से काफी सराहना मिली। इस फिल्म में उनके साथ अभय वर्मा और मोना सिंह भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म 7 जून, 2024 को रिलीज हुई थी।

फिल्म रामायण में रणबीर संग दिखेंगे यश

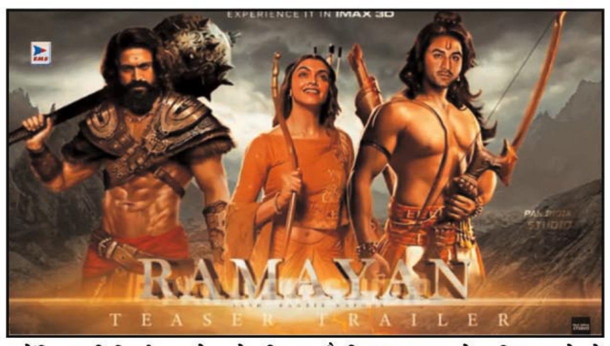

मुंबई (ईएमएस)। बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू कर दी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस भव्य फिल्म में यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। हाल ही कन्नड़ सुपरस्टार यश सेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने दो दिन तक कॉस्ट्यूम ट्रायल किया और फिर युद्ध के दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी। यह दृश्य मुंबई के अक्सा बीच पर फिल्माए जा रहे हैं, जहां बड़े स्तर पर एक्शन कोरियोग्राफी और वीएफएक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद, फिल्म की आगे की शूटिंग दहिसर के एक स्टूडियो में होगी। हालांकि, इस चरण में रणबीर कपूर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ युद्ध से जुड़े सीन फिल्माए जा रहे हैं, राम-रावण के आमने-सामने की लड़ाई नहीं। यश इस फिल्म में विशेष परिधानों में नजर आएंगे, जिन्हें डिजाइनर हरप्रीत और रिम्पल ने तैयार किया है। उनके कपड़ों को असली सोने की जरी से बनाया गया है, ताकि लंका के सोने के नगर जैसी भव्यता झलके। फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला भाग दीपावली 2026 और दूसरा भाग दीपावली 2027 में रिलीज होगा। यश, रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा लारा दत्ता, सनी देओल और इंदिरा कृष्णा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

एक्ट्रेस इशिता दूसरी बार प्रेग्नेंट, गूंजेगी किलकारी

मुंबई (ईएमएस)। एक्ट्रेस इशिता दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और उनका बेबी जुलाई 2025 में आने वाला है। अभिनेता वत्सल सेठ और इशिता दत्ता का पहला बेटा वायु अभी 19 महीने का है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वत्सल सेठ ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया, ह्लयह मेरे लिए एक सरप्राइज था, लेकिन बहुत अच्छा वाला सरप्राइज। जब इशिता ने मुझे प्रेग्नेंसी के बारे में बताया, तो मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन जब इस खबर को रजिस्टर कर लिया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।ह्व वत्सल ने बताया कि इशिता जब उनके पास आईं और यह खबर दी, तो उस वक्त उनका बेटा वायु बहुत ज्यादा क्रैंकी था। उन्होंने पहले इस खबर को समझने और इसे अपनाने में थोड़ा समय लिया, फिर परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर किया। वत्सल ने बताया कि वायु के लिए यह भी एक बड़ा सरप्राइज होगा कि वह जल्द ही बड़ा भाई बनने वाला है।

उन्होंने कहा, ह्लइस बार चीजें पहली प्रेग्नेंसी से काफी अलग हैं। एक पिता के तौर पर मेरी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इशिता और मैंने तय किया है कि जब दूसरा बेबी आएगा, तो मैं वायु का ध्यान रखूंगा और इशिता नए बेबी का। फिलहाल, दोनों अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में व्यस्त हैं। इशिता अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही हैं, जबकि वत्सल कुछ एंडोर्समेंट्स में बिजी हैं।

विशाल ददलानी की सीएम योगी को खुली चुनौती

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सिंगर और संगीतकार विशाल ददलानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। हाल ही में महाकुंभ के पानी में फेकल बैक्टीरिया पाए जाने के दावों को सीएम योगी ने खारिज कर दिया था और संगम के पानी को पीने योग्य बताया था। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए विशाल ददलानी ने सीएम योगी से कैमरे के सामने नदी का पानी पीने की चुनौती दी है।

विशाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा नफरत करने वालों की चिंता मत करो, सर। हमें आप पर भरोसा है। कृपया आगे बढ़िए और एक बढ़िया चंकी गिलास लीजिए। सीधे नदी से कैमरे पर। विशाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, तो कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और गंगा-यमुना के जल की स्वच्छता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम योगी या स-रकार की तरफ से विशाल ददलानी की इस चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।

राजा कुमारी का नया एल्बम काशी टू कैलाश रिलीज

मुंबई (ईएमएस)। हाल ही में मशहूर सिंगर राजा कुमारी का नया एल्बम काशी टू कैलाश रिलीज हुआ है। महा शिवरात्रि के अवसर पर रिलीज हुए इस एल्बम को उन्होंने समर्पण का परिणाम बताया। यह एल्बम भगवान शिव से प्रेरित एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रोजेक्ट है, जिसमें उनकी भक्ति, आस्था और जीवन में आए परिवर्तन को दशार्या गया है। राजा कुमारी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि भगवान शिव ही उन्हें इस ओर लेकर आए। उन्होंने बताया, यह एल्बम मेरे लिए बेहद खास है। दो साल पहले मेरा एक सफर अचानक कैंसिल हो गया, और तभी से मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद मैं केदारनाथ मंदिर जाने लगी। जब मैं शिव के सामने खड़ी हुई, तो मैंने पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और उनका जवाब स्पष्ट था - समर्पण। एल्बम में उनकी शास्त्रीय जड़ों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, विशेष रूप से द डिस्ट्रॉयर ट्रैक में। राजा कुमारी ने बताया कि शिव तांडव हमेशा से उनके पसंदीदा नृत्यों में से एक रहा है। बचपन में मिले शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रशिक्षण को भी उन्होंने इस एल्बम में शामिल किया है। उन्होंने संस्कृत छंदों का सही उच्चारण सुनिश्चित करने के लिए गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि उनका मानना है कि जब शब्दों को सही ढंग से उच्चारित किया जाता है, तो वे एक अलग ऊर्जा पैदा करते हैं। महा-शवरात्रि राजा कुमारी के लिए बेहद खास त्योहार है। उन्होंने बताया, मैं इस अवसर पर ध्यान लगाती हूं और मुझे इससे बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं शिव और पार्वती की प्रेम कहानी से भी बहुत प्रेरित हूं, जिसने मुझे 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए प्रेरित किया।

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की चर्चा

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में आ गई है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं। अब गोविंदा और सुनीता के तलाक की बातें चल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता 38 साल की शादी के बाद अलग होने की योजना बना रहे हैं। दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गोविंदा का एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि, अब तक गोविंदा या सुनीता की ओर से तलाक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गो-विंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड में एक लोकप्रिय जोड़ी है, लेकिन अब उनके तलाक की चर्चा से फैंस हैरान हो गए हैं।

मिलिंद सोमन की जबरदस्त फिटनेस

बॉलीवुड के सबसे फिटनेस फ्रीक एक्टर्स में शुमार मिलिंद सोमन अपनी जबरदस्त फिटनेस से हर किसी को चौंकाते रहते हैं। 59 साल की उम्र में भी वह अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल से युवाओं को टक्कर देते हैं। उनकी फिटनेस का राज कोई जादू नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनु-शासन और नियमित वर्कआउट है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं। इस वायरल वीडियो में मिलिंद सोमन जबरदस्त एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। वह नंगे पैर दौड़ते हुए दिख रहे हैं और अपनी बॉडी बैलेंसिंग का भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में उनकी फिटनेस और स्टैमिना देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी इस ऊर्जा और अनुशासन की जमकर सराहना कर रहे हैं। मिलिंद सोमन हमेशा से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहे हैं। वह अक्सर फिटनेस से जुड़े वीडियो और टिप्स शेयर करते हैं, जिससे फैंस को भी हेल्दी लाइफ जीने की प्रेरणा मिलती है। उनका यह नया वीडियो एक बार फिर साबित कर रहा है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है।

गुरु अनिरुद्धाचार्य द्वारा रणवीर की निंदा

फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहबादिया हाल ही में अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दौरान एक प्रतियोगी से बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। रणवीर ने प्रतियोगी से पूछा, क्या आप अपने माता-पिता को जीवनभर हर दिन सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे या फिर एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? उनके इस सवाल ने दर्शकों को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर उन्हें कड़ी फटकार मिल रही है। अब इस पूरे विवाद पर गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे रणवीर इलाहबादिया की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल हमारी संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ हैं और युवा पीढ़ी को ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। इस विवाद के बाद रणवीर इलाहबादिया ने अब तक कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन उनकी छवि पर इसका गहरा असर पड़ता दिख रहा है। फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उनके खिलाफ ना-राजगी जाहिर कर रहे हैं।

शादी समारोह में गोलगप्पों का खूब लुत्फ लिया श्रद्धा कपूर ने

मुंबई (ईएमएस)। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने एक शादी समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने जमकर गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। इस खास मौके की एक्ट्रेस ने तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, जिसमें वह ब्राउन कलर के एथनिक आउटफिट में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उन्हें पानी पूरी खाते हुए देखा जा सकता है, जिससे जाहिर होता है कि वह गोलगप्पों की कितनी बड़ी फैन हैं। तस्वीरों के साथ श्रद्धा ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, गिनना भूल गई फिर याद आया शादी में तो पानी पूरी अनलिमिटेड होती है। पानी पूरी लवर्स! उनकी इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान आकर्षित कर लिया और लोग कमेंट्स में अपनी पसंदीदा स्ट्रीट फूड डिश पर चर्चा करने लगे। श्रद्धा कपूर अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस का मनोरंजन करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह एक कटोरे में पपीता लिए बैठी थीं। इस पोस्ट में उन्होंने अपने फैंस से पूछा था कि क्या उन्होंने उसमें चाट मसाला डाला है या नहीं? बाद में उन्होंने एक और तस्वीर शेयर कर खुलासा किया कि उन्होंने पपीते पर चाट मसाला डाला था और लिखा, भगवान ने पपीता चाट मसाला के साथ खाने के लिए ही बनाया है।

फिल्मी दुनिया की बात करें तो श्रद्धा कपूर को आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका (महिला) पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस कैटेगरी में उनके साथ आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, यामी गौतम और नितांशी गोयल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। आईफा अवॉर्ड्स का आयोजन इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने वाला है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल होंगे। श्रद्धा कपूर अपनी क्यूटनेस और एनर्जी के लिए फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनकी यह मस्तीभरी पोस्ट इस बात का सबूत है कि वह हर छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढती हैं और उसे अपने चाहने वालों के साथ साझा करना पसंद करती हैं। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग बल्कि अपनी खाने की पसंद को लेकर भी चर्चा में रहती हैं।

साहित्य के क्षितिज पर नई ऊंचाइयां छू रही ट्विंकल खन्ना

मुंबई (ईएमएस)। मशहूर लेखिका और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना अपने नवीनतम पुस्तक वाचन सत्र के लिए यहां पहुंचीं। रैफल्स उदयपुर के भव्य राइटर्स बार में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों का हुजूम उमड़ पडा। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना, जो कभी बॉलीवुड में स्टारडम की चमक थी, अब साहित्य के क्षितिज पर नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उनकी नवीनतम किताब वेलकम टू पैराडाइज के कुछ अंश जब उनकी आवाज में गूंजे, तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। किताब के शब्दों और ध्वनिक संगीत के सुरों ने ऐसा समां बांधा कि कुछ लोगों को लगा मानो अगले ही पल बैकग्राउंड में कोई डांस सीक्वेंस भी शुरू हो जाएगा! राइटर्स बार की साज-सज्जा भी किसी भव्य फिल्मी सेट से कम नहीं थी–औपनिवेशिक शैली की भव्यता, झूमरों की मद्धम रोशनी और 3,000 से अधिक किताबों का समृद्ध संग्रह। पुस्तकालय में सजी किताबें भी जैसे वहां मौजूद लोगों को छेड़ते हुए कह रही थीं, अरे भाई, हमें भी पढ़ लो, सिर्फ सेल्फी मत लो! अपने लेखन यात्रा के बारे में बात करते हुए ट्विंकल खन्ना ने कहा, लेखन एक कला है, जिसमें कल्पना की चुटकी, व्यंग्य का तड़का और ह्यूमर की धीमी आंच पर पकाई गई कहानियां मिलाई जाती हैं। उनकी इस शैली ने श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि साहित्य में हास्य और व्यंग्य कैसे एक नई जान डाल सकते हैं। रैफल्स उदयपुर के महाप्रबंधक राजेश नाम्बी ने इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। वहां मौजूद साहित्यप्रेमियों की गहन चचाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी गंभीर सामाजिक मुद्दे का हल निकालने वाले हैं–या फिर बस यह तय कर रहे हैं कि चाय के साथ कौन सा स्नैक्स ज्यादा स्वादिष्ट रहेगा! कार्यक्रम के अंत में ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ दिए, और साहित्यिक संवाद के साथ-साथ हाई-टी का भी भरपूर आनंद लिया गया। वहां मौजूद लोग चाय की चु-स्कियों के बीच मन ही मन सोच रहे थे, अगर हर साहित्यिक आयोजन ऐसा हो, तो कौन कहेगा कि पढ़ाई-लिखाई बोरिंग होती है? रैफल्स उदयपुर में आयोजित इस सत्र ने यह साबित कर दिया कि जब साहित्य में ग्लैमर और ह्यूमर का सही मिश्रण हो, तो पढ़ना भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन सकता है।

सूडोकु नवताल- 7075

★★★★★ कठिनतम

				1			6	
					5			
2		3	9			8		
6							5	
			8		3			
	1							4
		7			1	3		9
			2					
	5			6				

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7074 का हल

7	6	8	2	1	9	3	4	5
2	1	5	6	3	4	8	7	9
3	4	9	5	7	8	6	1	2
5	7	4	8	6	1	9	2	3
9	2	1	3	4	5	7	8	6
8	3	6	7	9	2	1	5	4
1	5	3	4	8	5	2	9	7
4	9	7	1	2	3	5	6	8
6	8	2	9	5	7	4	3	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्दजाल - 7822

बं	न	गा	र	न	ब	ज	क	ब	ल	न
ब	ज	य	लि	दा	व	का	मौ	स	ल	य
ई	रा	ब	न	ज	वा	ज्यो	दा	बं	य	ना
का	ना	बं	र	ता	वी	ब	ति	ल	न	भि
म	इ	दि	म	स	रा	द	श	न	ब	रा
न	म	स्का	र	र	र	क	व	ना	श	म
न	बं	दि	श	वा	क	जी	र	ग	प	ब
व	र	न	ग	मा	व	सी	ब	न	प	न
नी	ब	ल	ज	न	बा	री	न	ज	प	र
त	मी	ल	प	बू	या	स	वी	ब	प	जा
का	न	न	व	नि	र्मा	ण	न	ग	प	बं

शब्द जाल में 'न' से शुरु होनेवाले 10 शब्द ढूंढिए. दिए गए शब्द उपर से नीचे एवं तिरछे भी हो सकते हैं.

नगमा, नजराना, नयनतारा, नवीन,नमस्कार, नयनाभिराम, नवज्योति, नवजीवन, नवनीत, नवनिर्माण,

शब्दजाल - 7821 का हल

दि	क	प्र	ग	बै	शी	ल	ब	ना	क	म
ती	ल	ती	ति	रा	क	क्रां	ति	ग	कृ	धु
क्षा	ज	दि	त	ग	ल	प्र	छ	ति	आ	म
ख	क	क	या	ज	रा	पु	मि	ल	न	ति
प	जो	क	का	द	ग	म	अ	प्र	तू	ग
झ	क	ग	प्र	ल	र्द	ह	औ	पू	ना	ण
घ	को	ती	न	षी	म	लि	जा	र	व	क
दे	व	दा	स	तै	ई	धा	या	क	श्या	लो
श	प	श्र	बा	हि	प्र	ई	क	प्र	री	म
प	जा	ही	र	न	या	दौ	र	र्त	ऐ	ता
प	प्र	द	क	प्र	प्र	है	या	रा	बा	प्र

Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग- 6775

7	5	6		4		1
	42		33	1	23	
1				3		2
2	25	3	34	7	39	6
		4			5	
	24	1	33		35	4
4	3		7	6	1	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 6774 का हल

1	2	3	4	5	6	7
6	22	1	30	2	38	4
2	3	4	5	6	7	1
7	30	2	38	3	33	6
3	4	5	6	7	1	2
5	39	7	43	4	25	5
4	5	6	7	1	2	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

एबी इनबेव ने 2032 तक बढ़ाई ओलंपिक साझेदारी

लुसाने

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सोमवार को घोषणा की कि वैश्विक शराब निर्माता एबी इनबेव ने अपनी विश्वव्यापी ओलंपिक साझेदारी (टॉप पार्टनरशिप) को 2032 तक बढ़ा दिया है।

शुरुआत में इस साझेदारी पर जनवरी 2024 में लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। अब यह साझेदारी 2030 शीतकालीन ओलंपिक (फ्रेंच आल्प्स) और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक तक विस्तारित कर दी गई है।

आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा, हम अपनी साझेदारी को 2032 तक बढ़ाने के लिए एबी इनबेव के साथ सहमत होकर प्रसन्न हैं। पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों का पहला अनुभव लेने के बाद, एबी इनबेव ने अपने कोरोना सेरो मार्केटिंग अभियानों के माध्यम से शानदार ओलंपिक जश्न मनाया, जिससे दुनियाभर के प्रशंसकों को खुशी मिली।

एबी इनबेव के सीईओ मिशेल डौकेरिस ने कहा, पेरिस 2024 ओलंपिक ने खेलों के वैश्विक महत्व और पहुंच को और मजबूत किया। हम आईओसी के साथ अपने संबंधों को 2032 तक बढ़ाने में प्रसन्न हैं और बीयर श्रेणी को सक्रिय रखते हुए खेल प्रशंसकों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं।

पैरालंपिक खेलों के अधिकार भी शामिल

इस समझौते के तहत आईओसी–आईपीसी दीर्घकालिक सहयोग समझौते के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) और पैरालंपिक खेलों के विपणन अधिकार भी शामिल हैं।

ओलंपिक टॉप पार्टनरशिप में 15 कंपनियां

आईओसी का टॉप पार्टनरशिप कार्यक्रम ओलंपिक प्रायोजन का उच्चतम स्तर है, जिसमें सीमित संख्या में कंपनियों को ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों के लिए श्रेणी–विशेष विपणन अधिकार मिलते हैं। वर्तमान में इसमें 15 भागीदार शामिल हैं। हाल ही में चीनी टेक ब्रांड टीसीएल ने घरेलू दृश्य–श्रव्य उपकरण और घरेलू उपकरण श्रेणी में 2032 तक शीर्ष भागीदार के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

ABInBev Official Partner

न्यूज ब्रीफ

चेन्नई सुपर किंग्स ने श्रीधरन को बनाया सहायक कोच

मुम्बई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) टीम ने आईपीएल के 2025 सत्र के लिए सहायक गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम को शामिल किया है। श्रीराम पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, और उन्होंने भारतीय टीम के लिए 2000 से 2004 के बीच आठ वनडे मैच खेले थे। हालांकि उन्हें भारतीय टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रभाव था और वे एक शानदार ऑलराउंडर रहे हैं। श्रीराम की नियुक्ति सीएसके के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी समझ और अनुभव सीएसके के बॉलर को और भी बेहतर बना सकता है। सीएसके पास महेन्द्र सिंह धोनी के अलावा रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, मथीशा पथिराना जैसे अहम खिलाड़ी हैं। सीएसके के प्रशंसकों में इस बार काफी उत्साह है सीएसके ने इस बार के मेगा नीमी में कई बड़े खिलाड़ी खरीदे हैं, जिनमें दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर अश्विन का नाम प्रमुख है। अश्विन के होने से गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। टीम के पास नए खिलाड़ी जैसे नूर अहमद, खलील अहमद, और राहुल त्रिपाठी भी हैं जिससे उसे काफी उम्मीदें हैं। सीएसके की टीम में कई अनुभवी और युवा खिलाड़ी हैं जिससे वह अलग–अलग परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। सीएसके के प्रशंसकों के लिए यह सत्र खास होने वाला है, क्योंकि टीम ने इस बार अपनी रणनीति को और भी मजबूत किया है। टीम का लक्ष्य 2025 आईपीएल में एक और खिताब जीतना है। टीम इस प्रकार है : रुतुराज गायकवाड़, पथिराना , शिवम दुबे , नूर अहमद, रविन्द्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, डेवोन कॉनवे, खलील अहमद, रचिन रवींद्र, एमएस धोनी,राहुल त्रिपाठी,अंशुल कंबोज,सैम करन।

वसीम अकरम ने कहा पाक टीम में बड़े बदलावों की जरुरत, चयन समिति पर भी सवाल उठाये

दुबई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे वसीम अकरम ने चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मिली हार के बाद अपनी टीम की जमकर आलोचना की है। अकरम ने कहा कि अब टीम में कई बड़े बदलाव करने होंगे। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो टीम हारती रहेगी। इसलिए 2026 विश्वकप की तैयारी अभी से करनी होगी। अकरम ने तेज गेंदबाजों को भी फटकार लगायी और कहा कि उनका प्रदर्शन काफी खराब था। अकरम ने ड्रेसिंग रूम शो में कहा, कठोर कदम उठाने की जरूरत है। हम सदियों से सफेद गेंद से पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। निडर क्रिकेटरों, युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करें। अगर आपको पांच–छह बदलाव करने हैं। तो वह भी करें। उन्होंने आगे कहा, आप अगले छह महीने तक हारते रहेंगे। यह ठीक है, लेकिन अभी से 2026 विश्व टी20 के लिए टीम बनाना शुरू कर दीजिए। अकरम ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की भी आलोचना करते हुए कहा कि उनका एकदिवसीय क्रिकेट में दूसरा सबसे खराब औसत है। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया। आपने उन्हें स्टार बना दिया है। पिछले पांच एकदिवसीय मैचों में पाक गेंदबाज 60 की औसत से केवल 24 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रति विकेट 60 रन उन्होंने कहा, हमारा औसत ओमान और अमेरिका से भी खराब है। एकदिवसीय खेलने वाली 14 टीमों में पाकिस्तान का गेंदबाजी औसत दूसरा सबसे खराब है।

सिद्धू ने विराट की जमकर प्रशंसा की

दुबई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह आने वाले समय में 10 से 15 शतक और लगा सकते हैं। सिद्धू ने कहा कि विराट ने जिस प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया उससे पता चलता है कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बचा है। भारत के पावरप्ले में एक विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने दबाव के हालातों में भी शतक लगा दिया। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, चरित्र संकट में नहीं बनता बल्कि दिखता है। विराट जोश और जुनून से भरा हुआ है और इस शतक के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह व्यक्ति अगले 2 या 3 साल तक खेलेगा और वह 10 या 15 शतक और लगाएगा। किसी के लिए भी सबसे बड़ा परीक्षण यह है कि वह कठिन समय से कैसे गुजरता है और वह कैसे कठिनाइयों को अपनाता है। सिद्धू ने कहा, पिछले छह महीनों में इतना कुछ हुआ है कि उसने अपना पल चुन लिया।

सोफिया में 76वें स्ट्रैंड्जा बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आगाज, भारत ने नहीं लिया हिस्सा

सोफिया

यूरोप के सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट स्ट्रैंड्जा मेमोरियल के 76वें संस्करण की शुरुआत सोमवार को सोफिया स्पोर्ट्स हॉल में हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 22 देशों और क्षेत्रों के 222 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिनका लक्ष्य रविवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाना है। बल्गारिया के युवा और खेल उप मंत्री पेटार म्लादेनोव ने टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए कहा, स्ट्रैंड्जा सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल भावना और परंपरा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मुक्केबाजी में विश्वास करना क्या होता है।

बल्गेरियाई बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कसीमिर इनिंस्की ने उम्मीद जताई कि यह टूर्नामेंट उच्च स्तर का रहेगा और सभी मुक्केबाजों के लिए एक शानदार अनुभव होगा। उन्होंने सभी एथलीटों और उनके कोचों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी खिलाड़ी चोटिल न हो।

भारत ने नहीं भेजी टीम, चीन के 9 मुक्केबाज मैदान में

इस बार भारत के मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि चीन की ओर से छह पुरुष और तीन महिला मुक्केबाज मुकाबले में उतरेंगे। सोमवार को चीन के वु युनबदारी ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में बुल्गारिया के टिंको बानाबाकोव के खिलाफ मुकाबला किया, लेकिन उन्हें 3–2 से हार का सामना करना पड़ा।

टूर्नामेंट में अगले कुछ दिनों तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां शीर्ष मुक्केबाज खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगे।

भारत, न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में, पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहर

नई दिल्ली। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड की बांग्लादेश पर पांच विकेट से जीत के साथ ही भारत ने सोमवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है, भारत के साथ ही न्यूजीलैंड भी अंतिम चार में पहुंच गया है, जबकि मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहर हो गए हैं। 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप–स्टेज गेम यह निर्धारित करेगा कि कौन सी टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर होगी। मैच का विजेता सेमीफाइनल में ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से खेलेगा। यह छठा संस्करण है जहां मेन इन ब्लू ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वे 1998, 2000, 2002, 2013 और 2017 में अंतिम चार में पहुंचे। न्यूजीलैंड के लिए, यह चौथा सेमीफाइनल होगा और 2009 के बाद यह पहला होगा।

स्टेला चेसांग टीसीएस लंदन मैराथन 2025 में लेंगी हिस्सा

कंपाला

युगांडा की स्टार एथलीट स्टेला चेसांग 27 अप्रैल को होने वाली टीसीएस लंदन मैराथन 2025 में हिस्सा लेंगी। युगांडा एथलेटिक्स फेडरेशन (यूएएफ) के अध्यक्ष डोमिनिक ओटुचेट ने सिन्हुआ से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुरुष वर्ग में जैकब किप्लिमो और महिला वर्ग में चेसांग युगांडा का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ओटुचेट ने कहा, हम अपने एथलीटों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि वे बेहद अनुभवी धावक हैं।

2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर का स्वर्ण पदक जीत चुकीं 28 वर्षीय चेसांग को लंदन मैराथन में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने केन्या की मौजूदा चैंपियन पेरेस जेपचिरचिर और विश्व रिकॉर्ड धारक रूथ चेपनगेटिच जैसी दिग्गज एथलीट होंगी।

इसके अलावा, दो बार की बर्लिन मैराथन चैंपियन टाइगिस्ट अस्सेफा (इथियोपिया) और ओलंपिक मैराथन विजेता सिफान हसन (नीदरलैंड्स) भी खिताब के लिए मजबूत दावेदार होंगी।

चेसांग ने अपनी तैयारियों को लेकर कहा, मैं इस मैराथन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं और कड़ी मेहनत कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतियोगिता बेहद चुनौतीपूर्ण होगी।

गौरतलब है कि चेसांग ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने के अलावा विश्व क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप में 10वां स्थान हासिल किया था। वह 2016 रियो ओलंपिक में युगांडा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 10,000 मीटर एवं हाफ मैराथन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं।

कमल चावला ने ऑल इंडिया स्नूकर खिताब जीता

6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन कमल चावला ने नेशनल स्नूकर चैम्पियन पारस गुप्ता को एकतरफा 6–0 से हराकर आरआर स्नूकर पाईंट ऑल इंडिया स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। साथ ही कमल ने टूर्नामेंट में 130 अंकों का सबसे बडा ब्रेक भी अपने नाम किया। 9 दिवसीय स्पर्धा का आयोजन स्टेशन एरिया स्थित आरआर स्नूकर पॉइंट द्वारा किया गया। राजधानी भोपाल के कमल चावला ने खिताबी मुकाबले में प्रतियोगिता में अपनी ख्याति के अनुरूप खेलते हुए युवा पारस गुप्ता को 6–0 से हराकर खिताबी जीत अपने नाम की। विगत माह पारस ने कमल चावला को नेशनल 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पराजित किया था।

संशोधित–एटीपी रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंचे आंद्रे रुबलेव

नई दिल्ली

दोहा में खेले गए कतर ओपन के फाइनल में आंद्रे रुबलेव ने ब्रिटेन के जैक ड्रेपर को 7–5, 5–7, 6–1 से हराकर अपना दूसरा कतर ओपन खिताब जीता। इस जीत के साथ ही नवीनतम एटीपी रैंकिंग में रुबलेव को एक स्थान का फायदा हुआ और वह नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि, फाइनल में हारने के बावजूद, 23 वर्षीय ड्रेपर ने एटीपी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 12वीं रैंकिंग हासिल की।

लेहेका, बेज और अन्य खिलाड़ियों की रैंकिंग में बढ़ोतरी

चेकिया के जिरी लेहेका, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 3 कार्लोस अलकराज को हराया था, तीन स्थान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस बीच, अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बेज ने रियो ओपन का सफलतापूर्वक बचाव किया और 31वें स्थान पर बने हुए हैं। उनके हमवतन कैमिलो उगो काराबेली और फ्रांसिस्को कोमेसाना, जो सेमीफाइनल में हार गए थे, ने लंबी छलांग लगाकर क्रमश: 69वें और 67वें स्थान पर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की।

शीर्ष 100 में अन्य उल्लेखनीय बढ़त

फ्रांस: गियोवन्नी म्पेत्शी पेरिकार्ड (29वें) और एलेक्जेंडर मुलर (41वें)

स्पेन: पेड्रो मार्टिनेज (36वें)

बेल्जियम: ज़िज़ौ बर्ग्स (56वें) और राफेल कोलिग्नन (98वें)

सर्बिया: हमाद मेदजेदोविक (71वें)

पुर्तगाल: जेमी फारिया (87वें)

शीर्ष 5 एटीपी रैंकिंग (अंक सहित)

- 1. जननिक सिनर (इटली) – 11,330
- 2. अलेक्जेंडर ज्वेरेव (जर्मनी) – 8,135
- 3. कार्लोस अलकराज (स्पेन) – 7,510
- 4. टेलर फ्रिट्ज (यूएसए) – 4,900
- 5. कैस्पर रूड (नॉर्वे) – 4,325

टेनिस जगत में इस हफ्ते की एटीपी रैंकिंग में कई बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नए सि तारों ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया।

रोहित और शमी अगले मैच में खेलेंगे : श्रेयस अय्यर

मुम्बई

बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि कप्तान रोहित शर्मा और तेज मोहम्मद शमी फिट है और अगले मैच खेलेंगे। श्रेयस ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की बातें सही नहीं हैं।वहीं मोहम्मद शमी की पिंडली में दर्द ठीक है। इन दोनों खिलाड़ियों की चोट के बाद प्रशंसकों की चिंताएं बढ़ गई थीं। पाकिस्तान की पारी के अंतिम ओवरों में जब रोहित गेंद पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, तो उन्हें असहज देखा गया था। तभी से ये आशंका हुई कि कप्तान को हैमस्ट्रिंग से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस दौरान रोहित काफी देर तक मैदान से बाहर रहे पर अय्यर ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि रोहित ने अपनी चोट के बारे में चिंता जताई थी, लेकिन वे सहज थे और इसे ज्यादा गंभीर नहीं मानते थे।

वहीं शमी को पिंडली में दर्द महसूस हुआ, जिसके कारण उन्हें उपचार के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। शमी अब बेहतर महसूस कर रहे थे और उनकी स्थिति स्थिर थी।

मैच के बाद श्रेयस अय्यर से इन दोनों खिलाड़ियों की चोट पर सवाल पूछा गया। उन्होंने दोनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करने के बजाय यह कहा कि उनकी चोटों को लेकर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ी ठीक हैं और कोई समस्या नहीं है। मैंने उनसे बात की थी और वे दोनों ही इस बारे में बहुत सहज थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश भारतीय टीम का अगला मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड से होने वाला है।

कुलदीप को आने वाले मैचों में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

दुबई। भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में अच्छी गेंदबाज करने से उत्साहित हैं। कुलदीप ने इस मैच में तीन विकेट लेकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। कुलदीप ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी प्रभावी गेंदबाजी की थी हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। कुलदीप ने अपनी लय हासिल कर ली है और उन्हें उम्मीद है कि अब वह इस टूर्नामेंट के बाकि मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुलदीप पिछले साल स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद से ही तीन महीने से अधिक समय तक खेल से दूर रहे थे। इस कारण उनकी फार्म को लेकर संदेह जताया जा रहा था। कुलदीप ने कहा, ' सर्जर के बाद फिट होने में तकरीबन छह महीने लगते हैं। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ दो मैच खेले। उनमें मेरी लय अच्छी थी। बांग्लादेश के खिलाफ भी मेरी लय अच्छी थी। कुलदीप पहले मैच में विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा, 'लेकिन स्वाभाविक है कि आप हमेशा विकेट हासिल करने की तलाश में रहते हैं। पाक के खिलाफ जब मैंने अपना पहला ओवर डाला, तो मुझे लगा कि मैं बेहतर लय में हूं। मैं आरामदायक स्थिति में हूं। कुलदीप ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं इससे भी बेहतर गेंदबाजी कर सकता हूं। मैंने चोट से वापसी करने के बाद अभी तक तीन–चार मैच खेले हैं।

मुख्यमंत्री ने विकसित असम के लिए आई-वे का दिया सुझाव, कहा-

राज्य सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक नया असम बनाने के लिए प्रतिबद्ध

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसमिशन के युग में, कनेक्टिविटी प्रगति की जीवन रेखा है, और असम तेज गति के विकास को प्राप्त करने के लिए इस क्रांति का नेतृत्व करने में दृढ़ है। मंगलवार को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में विकसित असम के लिए आई-वे नामक विषयगत सत्र में अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि असम भारत सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ डिजिटल क्रांति में एक मजबूत हितधारक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अब एक अभूतपूर्व डिजिटल क्रांति देख रहा है। क्रांति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उन्होंने राज्य भर में साइबर फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए अपनी सरकार की योजना प्रस्तुत की। डेटा की लगातार बढ़ती जरूरत पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा असम में एआई सक्षम डेटा सेंटर और एचडीएफसी द्वारा इसी तरह का डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि हाई स्पीड डेटा की जरूरत होगी। इसलिए, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ब्रह्मपुत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से ऑप्टिकल फाइबर लाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एक बार साकार होने पर, यह असम में तेज और विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि बीपीओ अपने ठिकानों को टियर 1 शहरों से टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए आने वाले दो से तीन वर्षों में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जैसे शहरों में कई बीपीओ होंगे और इसके परिणामस्वरूप हाई स्पीड डेटा की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के परिवर्तनकारी लक्ष्य के साथ डिजिटल इंडिया मिशन का नेतृत्व किया था। डॉ. शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण की सराहना की कि डिजिटलीकरण का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और समाज के सबसे वंचित वर्ग का भी उत्थान हो। उन्होंने यह भी कहा कि असम सरकार की 25,250 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस परियोजना को जल्द ही पूरा करने में मदद करें, ताकि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को लाभ मिल सके। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी रोडमैप के अनुसार असम सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो असम के डिजिटल परिदृश्य को बदलने के लिए एक मजबूत नींव रखे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आई-वे से विकसित असम का मार्ग प्रशस्त करना है, नए अवसरों को खोलना है और पूरे राज्य में समग्र विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को गति देने, शिक्षा को बढ़ाने और शासन में सुधार करने में आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने डिजिटल डिवाइड को पाटने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और पूरे राज्य में दूरसंचार सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन क्षेत्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं।

रेल मंत्री वैष्णव ने रेलवे और आईटी पहलों की घोषणा की

गुवाहाटी (हि.स.)। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा एक सत्र के दौरान व्याख्यान दिया। इस सत्र के दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा तथा असम के कई वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव, पूसीरे के महाप्रबंधक (निर्माण) अरुण कुमार चौधरी तथा वरिष्ठ रेल अधिकारी भी उपस्थित थे। रेल मंत्री ने रेलवे तथा आईटी उद्योगों से संबंधित कई नई पहलों और परियोजनाओं की घोषणा की, जो असम में विकास को काफी बढ़ावा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के विकास का *नया इंजन* है। बोडोलैंड समझौते के तहत एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए बोडोलैंड के बांसबारी में एक नया मेगा रेलवे कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे संचालन और अनुरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लामडिंग में इंजनों के लिए एक समर्पित मिड-लाइफ पुनर्निर्माण संयंत्र स्थापित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक विश्व स्तरीय सुविधा में तब्दील होने के दौर से गुजर रहा है, जिसमें तकनीकी नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 मंजिला आईटी पार्क शामिल है। असम में अगले 10 महीनों के भीतर दो अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू होंगी।

कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में 76 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर

गुवाहाटी। कामरूप महानगर जिला प्रशासन ने आज एडवांटेज असम के तहत कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। बैठक में कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला प्रशासन की ओर से जिला विकास आयुक्त पारिजात भुइयां ने भाग लिया। स्थानीय उद्योगों को और मजबूत करने के लिए मेसर्स दैवकी, मेसर्स चेराउगी रियल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओमश्री प्रोडक्ट्स, मेसर्स फर्स्ट. प्रो प्राइवेट लिमिटेड आदि के साथ 76 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में 219 परियोजनाएं हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हैं और 207 परियोजनाएं 50 करोड़ रुपए से कम मूल्य की हैं।

असम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की नींव रख रहा है : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में आयोजित *विकसित भारत के लिए असम में सेमीकंडक्टर क्षितिज को आगे बढ़ाना* विषयगत सत्र में भाग लिया। इस सत्र का उद्देश्य असम के सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर करना था जिसमें नवाचार, अवसंरचना विकास और निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया। इस सत्र में असम में सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य और भारत की व्यापक सेमीकंडक्टर रणनीति में इसकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य अत्याधुनिक तकनीक की नींव रख रहा है जो उद्योगों को आकार देगी, जीवन को बदलेगी और असम को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित जगीरोड में अत्याधुनिक ओएसएटी इकाई 2025 में उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके प्रतिदिन 48 मिलियन से अधिक चिप्स का उत्पादन करने की प्रभावशाली क्षमता है, जो एक गेम-चेंजर बनने के लिए तैयार है। इस परियोजना से 27 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए दरवाजे खुलने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और असम के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को असम में विशाल अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद् दिया, जहां सेमीकंडक्टर विनिर्माण असम के लिए उल्लेखनीय अवसर खोल सकता है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने अपने भाषण में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, निवेश प्रोत्साहन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने असम के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में असम की भूमिका को मजबूत करने के लिए एक और सेमीकंडक्टर प्लांट, जगीरोड में एनईआईएलआईटी विश्वविद्यालय परिसर और कामरूप जिले में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर शामिल हैं।

स्वास्थ्य परिदृश्य : स्वास्थ्य क्षेत्र के रूपांतरण पर विशेष सत्र आयोजित

गुवाहाटी (हि.स.)। एडवांटेज असम 2.0 - इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 के दौरान सोमवार को *स्वास्थ्य परिदृश्य: स्वास्थ्य क्षेत्र का रूपांतरण* विषय पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में असम में नवाचार, आधारभूत ढांचे के विकास और रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। सत्र की शुरुआत असम सरकार के आयुक्त और सचिव सिद्धार्थ सिंह के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों और विकास के अवसरों पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने राज्य सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, आधारभूत ढांचे में सुधार और डिजिटल हेल्थ पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि असम न केवल रोगी देखभाल में बल्कि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। सत्र में तीन अलग-अलग विषयों पर पैनल चर्चाएं हुईं, जिनका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त और सचिव डॉ. पी. अशोक बाबू ने किया। पहले सत्र में रोगी देखभाल और असम में नए अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें एसोचैम

धुबड़ी में 174.09 करोड़ रुपए का निवेश, 56 निवेशकों ने किया समझौता

धुबड़ी (हि.स.)। धुबड़ी जिले में मंगलवार को एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा सम्मेलन के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता धुबड़ी जिला आयुक्त दिबाकर नाथ ने की। बैठक में अतिरिक्त जिला आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान गुवाहाटी में चल रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद धुबड़ी जिले के विभिन्न उद्यमियों, व्यापारियों और विभागों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। धुबड़ी जिले में कुल 56 निवेशकों ने 174.09 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें: उद्योग विभाग में 26 निवेशकों ने 168.43 करोड़ रुपए का निवेश किया। पशुपालन विभाग में 5 निवेशकों ने 1.45 करोड़ रुपए का निवेश किया। कृषि विभाग में 5 निवेशकों ने 1.05 करोड़ रुपए का निवेश किया।

श्रीभूमि जिला प्रशासन ने निवेशकों के साथ 121 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

श्रीभूमि। चल रहे एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, श्रीभूमि जिला प्रशासन ने जिले के निजी निवेशकों के साथ 121 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। कुल 32 समझौता ज्ञापन निष्पादित किए गए, जिन्हें स्वीकृति के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा, जो व्यापार करने में आसानी की पहल के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। समझौता ज्ञापनों में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें वातित पेय और स्नैक्स, टाइल निर्माण, खाद्य और पेय पदार्थ, खदान और खनिज निर्यात, और लकड़ी के फर्नीचर निर्माण आदि शामिल हैं, जो औद्योगिक विकास के लिए जिले की क्षमता को रेखांकित करते हैं। निवेशकों को संबोधित करते हुए, जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी, आईएएस ने उद्यमियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन राज्य की औद्योगिक नीति के अनुरूप पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। आयुक्त द्विवेदी ने उभरते उद्यमियों को इस गति को भुनाने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। आयुक्त ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे को पहले ही संबोधित किया जा चुका है और कुछ और सबस्टेशनों की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन बैंकिंग संबंधी बाधाओं को हल करने के लिए नियमित अंतराल पर वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करेगा। गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का श्रीभूमि में कार्यक्रम में सीधा प्रसारण किया गया। प्रतिभागियों को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा के संबोधनों को देखने का अवसर मिला।

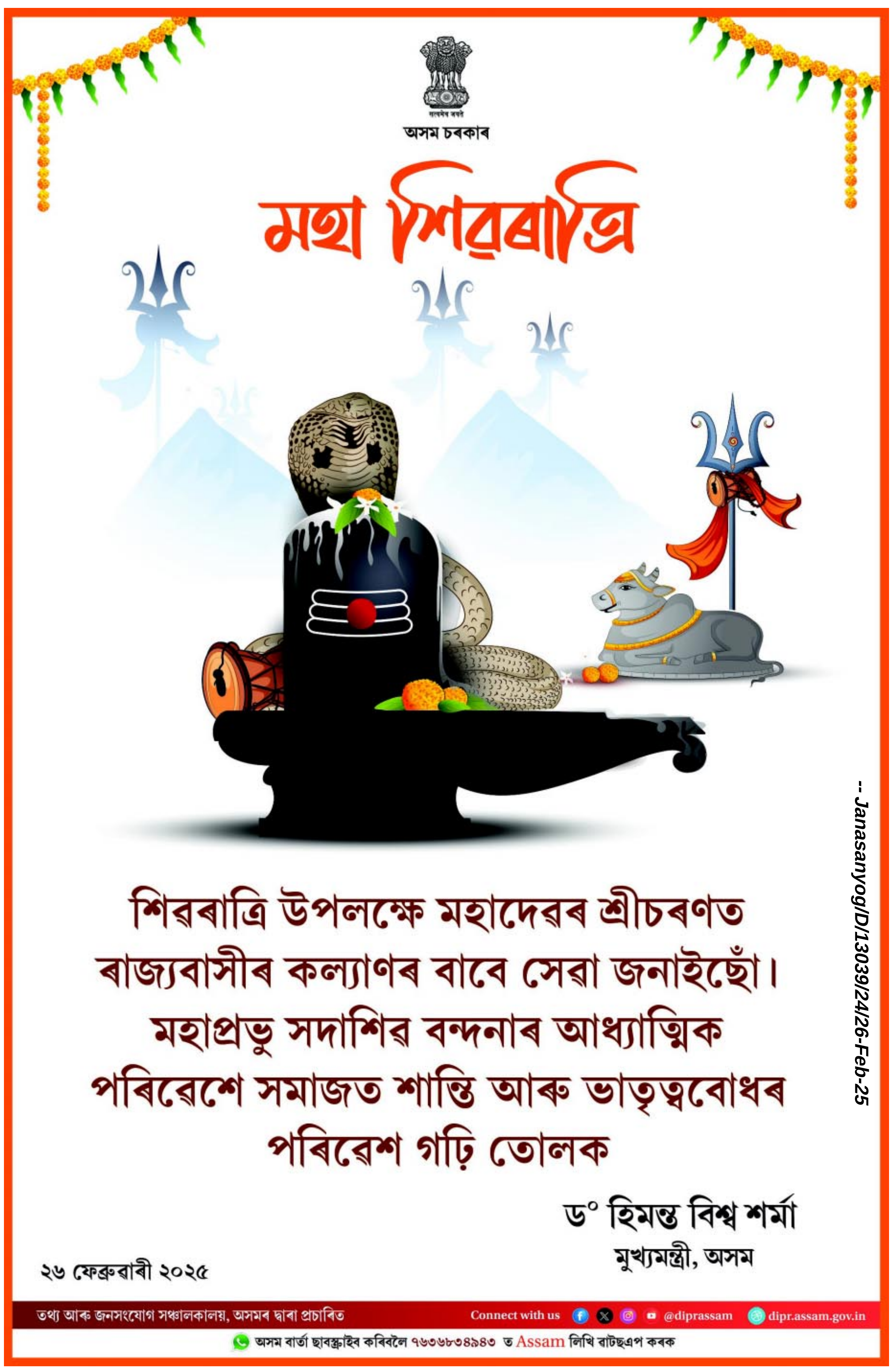

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**